हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

पूरी सूचना की उम्मीद

इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की कवायद स्वाभाविक ही थमने का नाम नहीं ले रही है और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता लगातार रंग ला रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि वह चयनात्मक नहीं हो सकता है, मतलब वह चुन-चुनकर सूचनाएं नहीं जारी कर सकता। उसे बॉन्ड से जुड़ी हर सूचना जनहित में जारी करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में एक-एक सूचना का सबके सामने आना तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है। बॉन्ड के संबंध में सूचनाओं की जितनी बड़ी खेप सामने आ चुकी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी खेप का आना शेष है। बैंक जैसे ही बाकी सूचनाएं देगा, वैसे ही चुनाव आयोग उनको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। दरअसल, अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट नंबर का खुलासा होना भी जरूरी है, इससे साफ तौर पर पता चलेगा कि बॉन्ड किसने खरीदा और उसका लाभ किसने लिया? देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी की झोली में कुल कितना चंदा गया है और किसने दिया है?

सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को यहां तक कहा है कि आप अगले आदेश की प्रतीक्षा मत कीजिए, जो भी सूचनाएं हैं, सबको जारी कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि एसबीआई चुनिंदा सूचनाएं ही जारी कर रहा है, यह पहलू एसबीआई के लिए ठीक नहीं है, इसका उसके ग्राहकों के बीच बेहद प्रतिकूल संदेश जा रहा है। तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बेशक, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पारदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी साख बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ही चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी और एसबीआई पर भरोसा किया गया था। अतः अब एसबीआई का दायित्व है कि वह इस भरोसे पर खरा उतरकर दिखाए। उसकी ओर से जब सारी सूचनाएं सामने आ जाएंगी, तब लोग यह परखने की स्थिति में होंगे कि अरबों के चंदे का लेन-देन कैसे सुलभ हुआ? राजनीतिक चंदा कतई अनैतिक नहीं है, पर उसमें पारदर्शिता का होना जरूरी है। बीत गए वे दिन, जब चंदे गोपनीय हुआ करते थे। चुनावों में काले धन का खूब प्रयोग हुआ करता था, पर आज के सूचना प्रधान दौर में लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए।

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक-एक सूचना का सबके सामने आना अब तय है और इसके लिए न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है।

इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जहां एसबीआई कठघरे में है, वहीं राजनीतिक पार्टियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या राजनीतिक पार्टियां स्वयं आगे बढ़कर यह नहीं बता सकतीं कि उन्हें कब किसने कितना चंदा दिया? इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, पर राज्यों में सत्तारूढ़ कुछ पार्टियों के जवाब हैरान करने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ पार्टियों की ओर से यह जवाब आया है कि उन्हें पता ही नहीं कौन चंदा दे गया? क्या ऐसे जवाब पर विश्वास कर लेना चाहिए? कायदा तो यही बोलता है कि राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए, पर ऐसी कोशिश को पार्टियां पहले खारिज कर चुकी हैं। शायद एक दिन आएगा, जब राजनीतिक पार्टियां स्वयं ही लोगों को पर्याप्त सूचनाएं मुहैया कराने लगेंगी और किसी भी नागरिक को सूचना के लिए अदालत जाने की नौबत नहीं आएगी।

चुनौतियों के बीच चुनाव एक मिसाल

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव पुलिस व दूसरे सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए थका देने वाली प्रक्रिया के साथ उनकी साख के लिए गंभीर चुनौती की तरह आते हैं।

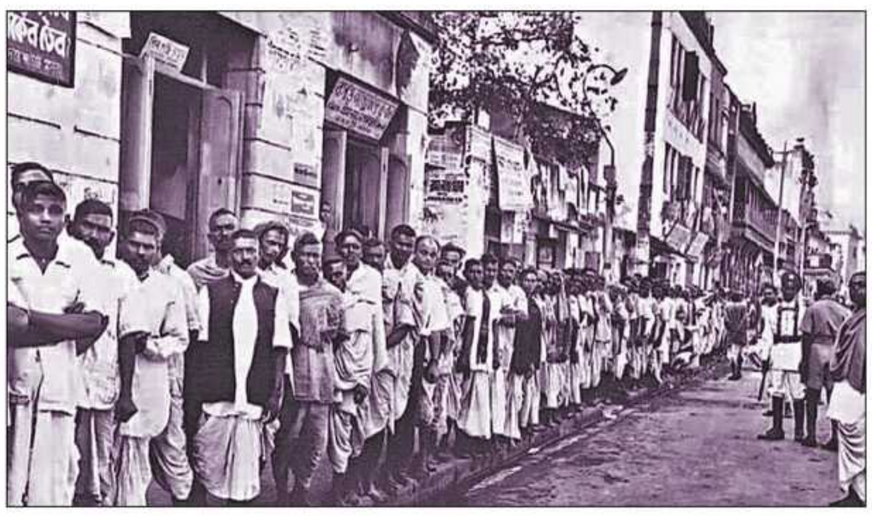

सोलह मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के साथ ही, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र (नब्बे करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले) में संघर्ष की रणभेरी बज उठी है। 4 जून की देर रात तक या उसके भी बाद, जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाएगी, यह संघर्ष पूरी शिद्दत के साथ चलता रहेगा। इसमें रहस्य, रोमांच, उत्सुकता और आशा-निराशा का द्वंद्व तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक 543 सीटों के लिए लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला नहीं हो जाता।

अपनी भौगोलिक, भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं के चलते भारतीय चुनाव दुनिया भर के पर्यवेक्षकों के लिए हमेशा उत्सुकता के विषय रहे हैं। खास तौर से पश्चिम के राजनीतिक पंडित तो शुरू से ही भारत मे चुनावों की सफलता और निष्पक्षता को लेकर सशंकित रहे हैं। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी सरकारें चुनने को लेकर भारतीय क्षमता के प्रति इतना आशंकित था कि वह मानता था कि अंग्रेजों के जाते ही यहां खून की बारिशें होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने पहला आम चुनाव जल्दी कराने की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिद पूरा करने के रास्ते में जिन बाधाओं का जिक्र किया था, उनमें से एक बाधा का उल्लेख ही उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ी समस्याओं को समझने में मददगार होगा।

चुनाव के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग की समझ तब गड़बड़ा गई, जब उन्होंने पाया कि एक क्षेत्र में कई सौ महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया था। इसके पीछे शिक्षा के अभाव के साथ-साथ वह सामाजिक परंपरा भी थी, जिसके तहत महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थीं। एक ने पति का नाम पूछने पर किसी प्राकृतिक अवयव की तरफ इशारा किया और फिर बाद में आने वाली सभी सिर्फ 'वही' के इशारे में सिर हिलाती गईं। दुर्गम भौगोलिक इलाकों वाले इतने विशाल देश में मतदान केंद्रों तक चुनाव कर्मियों को अपने साजो-सामान के साथ पहुंचाना, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना और फिर चुनाव समाप्त करा कर उन्हें वापस मुख्यालय लाना कितनी कठिन परीक्षा रही होगी, इसका तो आज अंदाज ही लगाया जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि सतरह लोकसभाएं इस प्रक्रिया से चुनी गई हैं और यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि हर चुनाव के बाद उत्तरोत्तर हिंसा की घटनाएं कम होती गईं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो आम तौर से चुनावी नतीजों को सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया है।

आठ दशकों में पसरे इस चुनावी सफर की कोई भी कहानी अधूरी ही रह जाएगी, यदि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख न किया जाए। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को चुनकर नेहरू जी लाए थे और अपनी सूझबूझ, मेहनत के बल पर उन्होंने एक ऐसी नींव डाली, जिसके बल पर वर्षों तक यह संस्था काम करती रही। स्वातंत्र्योत्तर भारत के शुरुआती दो दशक स्वप्नजीवी आदर्शों के दशक थे, पर साठोत्तरी भारत की कहानी सपनों से मोहभंग की कहानी है और इसके बहुत से असरात में से एक जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के रूप में दिखता है। चुनाव भी क्रमशः बाहुबल और धनबल का खेल होते चले गए। इनके लिए बदलते मूल्यों के साथ अक्षम और निष्क्रिय चुनाव आयोग मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा। आयोग आमतौर से सत्ताधारी दलों की धांधलियों पर अपनी आंखें मूंद लेता था।

निराशा के इस घटाटोप में अचानक एक ऐसे देवदूत का मंच पर प्रवेश हुआ, जो नौकरशाही में अपने प्रदर्शन से बहुत प्रभावित नहीं कर पाया था, पर एक सांविधानिक पद पर बैठते ही उसने एक मृतप्राय संस्था को प्रासंगिक बना दिया। वह व्यक्ति थे टीएन शेषन (1990-96)। बड़बोले, उतावले और अतिरेकी शेषन ने जो जबरदस्त सुधार चुनावी प्रक्रिया में किए, उनसे दूरगामी परिणाम निकले। यह कहना तो सरलीकरण होगा कि शेषन के सुधारों के बाद चुनावों में बाहु और धन की भूमिका खत्म हो गई, पर यह जरूर हुआ कि खुलेआम बूथ लूटने और पैसा बांटने के बेशर्म दृश्य अब पहले जैसे नहीं दिखते। दलों के साथ सरकारी मशीनरी में आयोग का भय भी बैठा, पर दुर्भाग्य से ये परिवर्तन व्यक्ति केंद्रित ही साबित हुए। तीन दशकों बाद धीरे-धीरे फिर चुनाव आयोग की भूमिका एक पक्षधर रेफरी की बनती जा रही है। यही कारण है कि शेषन और लिंगदोह जैसे आयुक्तों को छोड़ दें, तो शायद ही कोई जनता की स्मृति में बस पाया।

चुनाव पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए उबाऊ और थका देने वाली प्रक्रिया के साथ उनकी साख के लिए एक गंभीर चुनौती की तरह आते हैं। अब चुनाव कई महीनों में फैले सात-आठ चरणों में समाप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में जवान यात्राओं में बुरी तरह से थक जाते हैं और बाद के चरणों में उनके मनोबल और क्षमता पर इसका प्रतिकूल असर साफ दिखता है। मगर लंबी अवधि में फैले चुनावों का फायदा यह होता है कि मतदान केंद्रों पर अधिक बल उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण अब बूथ लूटने जैसी घटनाएं अतीत की चीज बन गई हैं। अब मतदाताओं को बूथ पर नहीं, वरन उनके गांवों, कस्बों या रास्तों में आतंकित किया जाता है। मुझे याद है कि एक जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में जब मैंने अपने करियर के पहले आम चुनाव में पुलिस प्रबंध किया था, तब मेरे जिले में सभी मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए एक-एक पुलिस कांस्टेबल भी उपलब्ध नहीं था, उनकी कमी होमगार्डों और चौकीदारों से पूरी करनी पड़ी थी। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, आज अगर बूथ पर गड़बड़ी होती है, तो उसका साफ मतलब तंत्र की मिलीभगत ही अधिक है।

चुनावों के लिए जरूरी समता या समानता भरे मैदान का हमारे देश में सतरह लोकसभा चुनावों के बाद भी अभाव दिखता है। सत्ताधारी पार्टी दौड़ शुरू होने के पहले ही आगे खड़ी हो जाती है। चुनावी बॉन्ड की जानकारियों या निर्वाचन आयोग के फैसलों से भी यह स्पष्ट है। इन सबके बावजूद इसे भारतीय मतदाता की प्रौढ़ता ही कहेंगे कि सारी गड़बड़ियों के बावजूद उसने अनेक बार सत्तारूढ़ पार्टियों को अपने मतदान के अधिकार से अपदस्थ किया है। आपातकाल के बाद का चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रूस में व्लादिमीर पुतिन की पांचवीं जीत के मायने

शशांक | पूर्व विदेश सचिव

रूस के राष्ट्रपति-चुनाव में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन को जीत मिली है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। चुनाव के पहले से कयास यही थे कि उनको कोई खास प्रतिरोध नहीं मिलेगा। वैसा ही हुआ है। करीब 87 फीसदी मत-प्रतिशत हासिल करके पुतिन अगले छह साल के लिए फिर से क्रेमलिन में पहुंच गए हैं। दिसंबर, 1999 के बाद से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में रूसी सत्ता के केंद्र में रहने वाले पुतिन इस बार कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे हैं। स्थिति यह है कि यूक्रेनी दावा वाले इलाकों में, जहां पर रूसी आबादी अधिक है, वहां भी चुनाव में उन्हें जीत मिली है।

यह चुनाव बताता है कि यूक्रेन युद्ध पर रूसी मतदाता पुतिन की नीति को सही मान रहे हैं। यह युद्ध चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। यही कारण है कि चुनाव की पूर्व-संध्या पर लोगों को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह उम्मीद जताई थी कि लोग उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समझेंगे और चुनौतियों से पार पाने के लिए कहीं अधिक एकजुट और आत्मविश्वासी बनकर उनके पक्ष में मत डालेंगे। अब जबकि चुनाव का परिणाम आ गया है, तो हो सकता है कि वह अपने कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बदल दें, ताकि युद्ध को आखिरी चरण में ले जाया जा सके। बेशक, चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने तीसरे महायुद्ध की आशंका जताई है, लेकिन कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक वह इस ज्वाला को शायद ही तेज करेंगे। रूस के लिए अमेरिकी चुनाव कितना अहम होता है, इसका एहसास इसी से कर सकते हैं कि पहले के अमेरिकी चुनाव में मास्को के हस्तक्षेप के आरोप उछले थे। हालांकि, इस बार पुतिन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों में उनकी कोई रुचि नहीं। फिर भी, माना यही जाना चाहिए कि अमेरिका की दशा-दिशा देखने के बाद ही रूस अगला कोई बड़ा कदम उठाएगा। हां, इस बीच पुतिन ऐसी नीति जरूर अपना सकते हैं कि यदि यूक्रेन आगे बढ़ता है, तो रूस अधिक आक्रामक होकर जवाब दे सके।

चुनाव जीतने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने तीसरे महायुद्ध की आशंका जताई है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक वह शांत ही रहेंगे।

पुतिन की सरपरस्ती में रूस ने खुद को कितना बदला है, इसके लिए मैं आपको पिछली सदी के आखिरी दशक में ले चलता हूं। मैं उन दिनों सेंट पीटर्सबर्ग में था। तब तक यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ गया था, और एक तरह से वह खुद को तीसरा ध्रुव बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। उधर, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस दूसरे ध्रुव के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा था। उसकी मंशा यूरोपीय देशों के साथ संस्थागत रूप से जुड़ने की थी। यह वही दौर था, जब व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार रूस की सत्ता संभाली थी। पुतिन की ताजपोशी के बाद रूस की नीति में एक बड़ा बदलाव यह आया कि उसने पूरब और पश्चिम, दोनों को देखना शुरू किया। इसका उसे फायदा भी मिला है। हालांकि, अब उसके लिए बीच का यह रास्ता करीब-करीब बंद हो चुका है। रूस भले आज भी यूरोपीय देशों को गैस बेच रहा है, पर यूक्रेन संकट के कारण उसकी आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है और पश्चिमी यूरोप की भी उस पर निर्भरता कम हुई है। पुतिन को अपने नए कार्यकाल में इस चुनौती से भी पार पाना होगा।

वैसे, भारत भी रूस के लिए काफी अहमियत रखता है। हमने यह देखा है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के नेताओं से बातचीत करके हमारे प्रधानमंत्री ने शांति बनाने का प्रयास किया था। हालांकि, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया से मास्को के रिश्ते बेहतर बन रहे हैं, लेकिन ये ऐसे देश हैं, जो खुद प्रतिबंधित होते रहे हैं। ऐसे में, भारत चाहे तो रूस से अपने आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में उसकी मदद ले सकता है। इसके लिए हमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके तहत रेलमार्ग, समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों का विकास करना अनिवार्य है। इजरायल-हमास युद्ध के कारण इसमें कुछ सुस्ती आई है, लेकिन लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमें अपने रास्ते तैयार करने ही होंगे। हमें अपने हितों को तवज्जो देते हुए कूटनीतिक पहल करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन का मौन जरूरी

यदि हम कुछ भी समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे मन को शांत होना चाहिए, जबकि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उसकी चिंता में डूब जाते हैं, है न? हम उसकी छान-बीन करने लगते हैं, उसके विश्लेषण में जुट जाते हैं, उसकी ऐसी-तैसी कर डालते हैं, और यह सब इस उम्मीद से कि हम उसको समझ पाएंगे। मगर क्या किसी मानसिक उठा-पटक के जरिये हम कुछ समझ पाते हैं? निश्चय ही, समझ तभी आती है, जब मन बिल्कुल खामोश होता है।

कहा जाता है, हम जितना अधिक भूख या युद्ध के प्रश्न से अथवा किसी भी मानवीय समस्या से जूझेंगे, उतना ही अधिक उसको समझ पाएंगे। क्या यह सच है? शताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं; व्यक्तियों के बीच, समाजों के बीच द्वंद्व बना हुआ है; आंतरिक और बाहरी जंग जारी है। क्या उस युद्ध का, उस द्वंद्व का निपटारा हम और अधिक द्वंद्व या संघर्ष से, किसी चालाकी भरे प्रयत्न से कर सकते हैं? हम समस्या को केवल तभी समझ पाते हैं, जब उसके सामने होते हैं, जब हम तथ्य का सामना कर रहे होते हैं और किसी तथ्य का सामना हम तभी कर पाते हैं, जब मन और तथ्य के बीच बाधा उत्पन्न करने वाला कोई विक्षोभ नहीं होता; अतः यदि हम समझना चाहते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं कि मन मौन हो?

आप कहते हैं, मेरा मन क्षुब्ध है, इसे कैसे शांत रखूं? क्या कोई पद्धति मन को शांत कर सकती है? क्या कोई अनुशासन इसको मौन कर सकता है? ऐसा किया जा सकता है; परंतु जब इस प्रकार मन को शांत बना दिया जाएगा, तो क्या वह मौन होगा, क्या निश्छलता होगी? या वह मन को किसी विचार, किसी सूत्र, किसी शब्दावली में जकड़ लेना होगा? ऐसा मन तो मृत मन होगा। अधिकांश व्यक्ति, जो तथाकथित आध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं, मृतप्राय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया होता है, शांत रहने के लिए उन्होंने अपने आप को किसी नुस्खे में कैद कर लिया होता है। स्पष्ट है, ऐसा मन कभी मौन नहीं होता, उसे केवल दमित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है।

जब व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है, जब मन मौन हो; यानी यदि मैं आपको समझना चाहूं, तो मुझे शांत होना होगा, मुझमें आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न हो।

मन केवल तभी मौन होता है, जब वह इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है, जब मन मौन हो; यानी यदि मैं आपको समझना चाहूं, तो मुझे शांत होना होगा, मुझमें आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न हो, मैं पूर्वाग्रहों से मुक्त रहूं, मुझे अपने समस्त निष्कर्षों, अनुभवों को हटाकर आपके समक्ष आना होगा। जब मन संस्कारग्रस्तता से मुक्त होता है, केवल तभी मेरे लिए समझ पाना संभव होता है। जब मैं इस बात के सत्य को देख लेता हूं, तभी मन मौन होता है, और तब यह प्रश्न नहीं उठता कि मन को शांत कैसे बनाया जाए?

जे कृष्णमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

आत्मनिर्भर महिलाएं आज समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं। देश को प्रगति के एक नए पथ पर ले जाने का सामर्थ्य भी इनमें खूब है। इनकी राह की सभी बाधाओं को दूर करना हमारा दायित्व है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 19 मार्च, 1949

आन्तरिक सुरक्षा

देश के भीतर शांति और व्यवस्था को कायम रखना किसी भी सरकार का पहला काम होता है। इसके बिना देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। भारत सरकार का वह विभाग जो देश की शांति और व्यवस्था से ताल्लुक रखता है, सरदार पटेल के कुशल हाथों में है। इस विभाग ने जिस प्रकार कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए अपने दायित्व को निभाया है, उसके लिए उसकी तारीफ ही करनी होगी। यही कारण है कि जब हिन्द की पार्लियामेंट में इस विभाग की खर्च की मांग मंजूरी के लिए पेश की गई तो अन्य मंत्रियों की तुलना में सरदार पटेल को बहुत कम आलोचना का सामना करना पड़ा। अवश्य ही पं. हृदयनाथ कुंजरू ने दो कटौती के प्रस्ताव पेश किये थे, उनमें से एक उन्होंने स्वयं वापस ले लिया और दूसरा पार्लियामेंट ने अस्वीकार कर दिया। पं. कुंजरू की शिकायत थी कि सरकार ने कम्यूनिस्ट पार्टी को उसकी तोड़-फोड़ और हिंसा की नीति के बावजूद गैर-कानूनी करार नहीं दिया। सरदार पटेल का इस बारे में यही उत्तर था कि सरकार फिलहाल उन कम्यूनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करना काफी समझती है जो गैर-कानूनी प्रवृत्ति में हिस्सा लेते पाये जाते हैं। किंतु जब कभी आवश्यक प्रतीत होगा तो वह कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कदम उठाने में भी संकोच न करेगी। पं. कुंजरू की दूसरी शिकायत प्रान्तीय रक्षा दलों के सम्बन्ध में थी। उनका खयाल है कि जब प्रान्तों में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है तो प्रान्तीय रक्षा दलों जैसे अर्द्ध सैनिक संगठनों पर क्यों निरर्थक व्यय किया जा रहा है? प्रान्तीय रक्षा दलों का उद्देश्य अच्छा है। यदि संगठन में खराबी पैदा हो गई है तो वह ध्यान दिलाये जाने पर दूर की जा सकती है।

देश की शांति और व्यवस्था के लिए साम्प्रदायिक शक्तियों की ओर से खतरा पैदा किया गया और भारत सरकार के गृह सचिवालय ने उस खतरे का दृढ़ता किंतु विवेक के साथ सामना किया है। जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित की थी, उस समय विभाजन के कारण देश का साम्प्रदायिक वातावरण अत्यन्त क्षुब्ध था और कुछ हिस्सों में जो दंगे-फसाद हुए, वे सरकार को खुली चुनौती थे। किंतु सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों पर काबू पाया और आज सरदार पटेल यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि देश की आन्तरिक शांति को कोई गंभीर खतरा नहीं रह गया है।

आमतौर पर आस्तिक ही ज्यादा भ्रमित

अनुलोम-विलोम

आस्तिक बनाम नास्तिक

ऐसा नहीं है कि मैं बगैर जाने ईश्वर को काल्पनिक कहता हूं। खूब अच्छी तरह जान-समझकर और जीवन का एक लंबा समय इस कल्पना पर बर्बाद करने के बाद कहता हूं। निश्चित रूप से ईश्वर नामक धोखे की असलियत जानता हूं। यह मेरा अहंकार नहीं, बल्कि मेरे अनुभव का नतीजा है। 30 से भी अधिक वर्ष धर्मग्रंथों के अध्ययन में बिताकर मैं नास्तिक बना हूं। मैंने आस्तिकों को कई बार देखा है कि वह ज्यादातर भ्रमित रहते हैं, और वे ईश्वर, जिसके लिए उनके ही धर्मग्रंथों में लिखा है कि 'परमात्मा बोधगम्य नहीं है, मन-बुद्धि और इंद्रियों तथा तर्क से भी परे है', उसके अस्तित्व को भी तर्क द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यानी, अपने ही धर्मशास्त्रों की बात नहीं मानते! ठीक है, यदि आप ईश्वर को मानते हैं, तो मानते रहिए, लेकिन कुतर्कों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में व्यर्थ ही किसी और का समय तो जाया मत करिए!

सवाल कई हैं। क्या ईश्वर विश्वास करने योग्य है? क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, जिसे हमने कभी देखा नहीं? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर किसी का विश्वास मत करना, नहीं तो वे तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, तो आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं? आपके पास तो भगवान का नंबर भी नहीं है, संपर्क का कोई तरीका नहीं है। जब कुछ अप्रिय दुर्घटना जीवन में घट जाती है, तब लोग चिल्लाते हैं, मेरा भरोसा टूट गया, अब विश्वास उठ गया भगवान पर से! आखिर आपने किस आधार पर भगवान से यह अपेक्षा रखी? ईश्वर ने क्या कभी इसका वायदा किया था? आस्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं समझता, परंतु बचपन से ही उसके अवचेतन ही नहीं, बल्कि अर्द्धचेतन या अविकसित चेतन मन में भय और लालच से ओत-प्रोत जिस आस्था का निर्माण किया जाता है, उसके चलते वह कहता है, पंचों की बात सिर माथे, पर लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा।

वैसे आप यह न समझिएगा कि मैं यहां किसी को नास्तिक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे लिए नास्तिकता एक अनुभव है, जो किसी दूसरे के कहने से नहीं, बल्कि तभी प्रत्यक्ष होता है, जब व्यक्ति स्वयं आस्तिकता के उस भ्रम और झूठ के आवरण से मुक्त होने के लिए सत्य संकल्पित हो, जो पैदा होने के समय से ही उसकी इच्छा के बिना उस पर मढ़कर, उसे हिंदू, मुसलमान इत्यादि बना दिया गया था!

बालेंदु गोस्वामी, टिप्पणीकार

नास्तिकों में अटल विश्वास की कमी

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश लोगों के लिए धर्म ईश्वर मीमांसा, पारलौकिक जीवन का विषय मात्र है, जबकि धर्म में न्याय, दंड, राजत्व, शक्ति संतुलन, सामाजिक संहिता, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, सामुदायिक चेतना, लाभांश का विभाजन जैसे वे तमाम आयाम हैं, जो जीवन से जुड़े हैं। आस्तिक का अर्थ मात्र ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना नहीं, बल्कि आस्तिक का अर्थ है अटल विश्वास। नास्तिकों में इसी की कमी होती है। आपकी दृष्टि में जो कुछ झूठ है, निराधार है, गलत है, फिर भी सामने वाला उस पर अटल विश्वास करता है, उस पर चलता है, निस्संदेह वही आस्तिक है।

वीपी सिंह सिसोदिया, टिप्पणीकार

एक अदृश्य सत्ता

जिस तरह, प्रकाश का अनुभव करने के लिए आंखों को खोलना जरूरी है, उसी तरह सच को जानने के लिए बुद्धि के कपाट को खोलना निहायत जरूरी है। इस प्रकाश से डरकर जो अपनी आंखें नहीं खोलेगा, उसके लिए संसार अंधकारमय ही रहेगा, ठीक उसी तरह, जिस तरह से नास्तिकों को हर वक्त ईश्वर में बुराई ही दिखती है। वास्तव में, धर्म का मार्ग संकरा जरूर है, लेकिन इससे गुजरना संभव है। जो लोग इससे निकल पाते हैं, वही अच्छे और बुरे का एहसास तटस्थ भाव से कर पाते हैं। संसार के रचयिता की जीवोद्धारक विधि बेहद अजीबोगरीब है। वह आपके अनुसार काम नहीं करता, बल्कि अपने मुताबिक हालात रचता है। जब ये हालात हमारे प्रतिकूल होते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि वास्तव में इन बुरे हालात में भी हमारे लिए सबक होते हैं। अगर हम उन हालात का सही से विवेचना कर सकें, तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मगर ऐसा हम करते कहां हैं? नास्तिक हमारी इसी सोच का फायदा उठाते हैं और हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अरुचि पैदा करने की कोशिश करते हैं। आस्तिक ईश्वर में विश्वास करने की बात कहते हैं, जिसका फायदा यह है कि आपको आत्मविश्वास मिलता है। जब कभी आप संकट में फंसे होते हैं, तो आपको एक ऊर्जा मिलती है और आप उस संकट से बाहर निकलने को तत्पर हो उठते हैं। निराशा आपको नहीं घेरती। मगर दुर्भाग्य से दुनिया में धर्म में अपनी स्पष्टता बढ़ाने के बजाय लोग भ्रमित होते रहते हैं। इस भ्रम से बचना वास्तव में आस्तिकता को बचाना है। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि एक अदृश्य ताकत है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और वही इसका संचालन कर रही है।

दीप्ति, टिप्पणीकार

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 19 मार्च 2024

एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। - बाल गंगाधर तिलक

व्लादिमीर पुतिन ने यह चुनाव जीतने के लिए लड़ा था और अंततः वह जीत भी गए। जल्द ही वह स्टालिन को पीछे छोड़ देश के 200 वर्षों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहने वाले नेता होंगे। देखने वाली बात होगी कि यह जीत वैश्विक व्यवस्था में पुतिन की भूमिका को कैसे सशक्त करती है।

पांचवीं बार पुतिन

व्लादिमीर पुतिन का पांचवीं बार रूस का राष्ट्रपति चुना जाना तय ही माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्हें यह जीत मिली है, उसका एक संदेश है। दरअसल, पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेलनी, जिनकी कुछ समय पहले जहर देकर हत्या कर दी गई थी, के समर्थकों द्वारा उनके खिलाफ चलाए जा रहे 'नून अगेंस्ट पुतिन' अभियान के अलावा रूस के विभिन्न शहरों व तमाम देशों में भी रूसी दूतावासों के समक्ष उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चले रहे थे। चुनाव में उनके प्रतिस्पर्धी भी खुद उनके द्वारा ही तय किए गए थे। एक प्रतिस्पर्धी नेता ने तो बीच चुनाव में ही पुतिन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। विरोधी परेशानी खड़ी न करें, इसका इंतजाम पहले ही कर दिया गया था। मतदान के दौरान पुरी सख्ती बरतने के बावजूद देश में कई जगहों से हिंसा की खबरें आती रहीं। जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन ने यह चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा था और अंततः वह जीत भी गए। अगर वह अपने छह वर्षों के कार्यकाल को पूरा करते हैं, तो सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए देश के 200 वर्षों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहने वाले नेता बन जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 1999 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन के इस्तीफा देने के बाद पुतिन पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर 2000 में राष्ट्रपति बने थे। सांविधानिक बाध्यता के चलते जब 2008 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने अपने साथी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए। संविधान संशोधन के जरिये पुतिन फिर 2012 और 2018 में राष्ट्रपति बने। फिर 2020 में किए गए संविधान संशोधन से उनका 2036 तक राष्ट्रपति बनने का मार्ग खुल गया है। जाहिर है कि ज्यादातर तानाशाहों की तरह पुतिन भी लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहते हैं। हालांकि इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिनायकवादी व्यवस्थाएं रूस के इतिहास और उसकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रही हैं। पिछले कुछ कार्यकालों में उनको मिले वोट एक दिलचस्प पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसके नतीजे हर बार उनके लिए बेहतर होते गए हैं। 2012 में उन्हें 63.6 फीसदी, राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल बढ़ाए जाने के बाद 2018 में 76.7 फीसदी और इस बार करीब 88 फीसदी वोट मिले। इससे यह भी साबित होता है कि तमाम आपत्तियों के बावजूद पुतिन रूस के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बने हुए हैं। देखना होगा कि यह जीत वैश्विक व्यवस्था में उनकी भूमिका को कैसे सशक्त बनाएगी।

जीवन धारा

रमण महर्षि

प्रबुद्ध ऋषि (ज्ञानी) का मन कभी ब्रह्म से अलग नहीं होता है। अज्ञानी का मन अभूतपूर्व दुनिया में प्रवेश करके दर्द और पीड़ा सहता रहता है। और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रह्म की ओर मुड़कर सुख का अनुभव करता है।

आनंद और आत्मा अलग-अलग नहीं हैं

***जो** आनंद है, वह आत्मा भी है। आनंद और आत्मा अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और केवल यही वास्तविकता है। संसार की असंख्य वस्तुओं में से किसी एक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे सुख कहा जाए। यह केवल अज्ञानता और मूर्खता के कारण है कि हम कल्पना करते हैं कि उन वस्तुओं से खुशी प्राप्त की जा सकती है। जब मन बाह्य चीजों में रम जाता है, तो उसे पीड़ा का ही सामना करना पड़ता है।*

सच तो यह है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो मन अपने स्रोत की ओर मुड़कर केवल उस खुशी का अनुभव करता है, जो स्वयं के लिए स्वाभाविक है। इसी प्रकार गहरी नींद में, आध्यात्मिक समाधि में, बेहोशी में, जब कोई इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है या जब किसी अवांछनीय मानी जाने वाली वस्तु से कोई अनिष्ट हो जाता है, तो मन भीतर की ओर मुड़ जाता है और आत्मा की खुशी का आनंद लेता है। इस प्रकार स्वयं को त्यागकर भटकना और बार-बार उसी की ओर लौटना मन की अंतहीन और थका देने वाली स्थिति है। पेड़ की छाया सुखद है और बाहर सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली है। धूप में मेहनत करने वाला व्यक्ति पेड़ की ठंडी छाया ढूंढता है और उसके नीचे खुश रहता है। कुछ देर वहां रहने के बाद वह चला जाता है, लेकिन सूरज की निर्दयी गर्मी को सहन करने में असमर्थ होने के कारण वह फिर छाया की तलाश करता है। इस प्रकार वह छाया से धूप और धूप से छाया की ओर घूमता रहता है। इस तरह से कार्य करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी छाया नहीं छोड़ता है। उसी तरह प्रबुद्ध ऋषि (ज्ञानी) का मन कभी ब्रह्म, पूर्ण से अलग नहीं होता है। दूसरी ओर, अज्ञानी का मन अभूतपूर्व दुनिया में प्रवेश करके दर्द और पीड़ा सहता रहता है। और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रह्म की ओर मुड़कर सुख का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है।

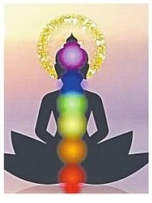

हालांकि यह अभूतपूर्व दुनिया विचार के अलावा कुछ और नहीं है। जब संसार उसकी दृष्टि से दूर हो जाता है, यानी जब वह विचार से मुक्त होता है, तो मन स्वयं के आनंद का लाभ उठाता है। इसके विपरीत जब संसार प्रकट होता है, तभी विचार उत्पन्न होता है और फिर मन दर्द और पीड़ा का अनुभव करता है। शांति आपकी स्वाभाविक अवस्था है। यह मन ही है, जो प्राकृतिक अवस्था में बाधा डालता है। आपका विचार केवल मन में ही बना है। मन क्या है, इसकी जांच करो, तो वह गायब हो जाएगा। विचार के अलावा मन जैसी कोई चीज नहीं है। फिर भी, विचार के उद्भव के कारण आप अनुमान लगाते हैं कि जिससे यह शुरू होता है, उसे मन कहते हैं। जब आप यह देखने के लिए जांच करते हैं कि यह क्या है, तो पाते हैं कि वास्तव में मन जैसी कोई चीज नहीं है। मन के गायब होने पर आपको शाश्वत शांति का एहसास होता है।

आनंद से परे...

सूत्र

आनंद सभी गतिविधियों से मुक्त और गहरी नींद के समान विज्ञान की स्थिति में शांति का अनुभव है। इसे केवल निर्विकल्प (अवधारणाओं के बिना रहना) की स्थिति भी कहा जाता है। आनंद से परे की अवस्था मन की निरंतर शांति की स्थिति है, जो पूर्ण शांति, जाग्रत-सुषुप्ति की स्थिति में पाई जाती है, जो गहरी नींद के समान होती है।

परिवार से रिश्ता पुराना है

भारतीय राजनीति का परिवार से उतना ही पुराना रिश्ता है, जितना देश की स्वतंत्रता का। नेहरू-गांधी परिवार भले ही दुनिया के सबसे स्थायी परिवार के रूप में बचा है, लेकिन इसकी थकी हुई विरासत प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रही है। भारतीय राजनीति इतनी उर्वर है कि अब भी कई परिवार सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं।

परिवार मायने रखता है। एक बुनियादी सामाजिक इकाई के रूप में परिवार राजनीति में विचारधारा को स्थायित्व की भावना देता है, जबकि सिद्धांत केवल निश्चितता प्रदान करते हैं। एक ऐसे युग में, जब दृश्य एवं अन्य संवेदी संचार चुनाव अभियान में लोगों की धारणाओं को प्रभावित करते हैं, हर कोई अपनी आदर्श पारिवारिक तस्वीर को भुनाना चाहता है। यह उन समाजों में अधिक होता है, जहां राजनीति में सार्वजनिक एवं निजी, दोनों तत्व घुले-मिले होते हैं।

राजनीति में सत्ता विरासत के रूप में परिवार से भी मिलती है। प्रतिभा और लोकप्रियता से ज्यादा रक्त-संबंध मजबूत बन जाता है। यह परिवार ही है, जो मायने रखता है, विचारधारा नहीं। राजनीतिक वंशवाद परिवार को सर्वोच्च एवं उन्नत संस्था के रूप में सम्मान देता है। यह उन परिवारों में होता है, जहां भरोसे का सबसे सच्चा स्वरूप लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध विकसित और संरक्षित किया जाता है।

एस प्रसन्नराजन
संपादक-ओपेन मैगजीन

भारतीय राजनीति का परिवार से उतना ही पुराना रिश्ता है, जितना देश की स्वतंत्रता का, और अगर कोई एक संविधानेतर संस्था है, जिसने लोकतंत्र के रूप में राष्ट्र की यात्रा को परिभाषित किया है, तो वह परिवार है। नेहरू-गांधी परिवार भले ही दुनिया के सबसे स्थायी परिवारों के रूप में बचा हो, इसके अंतिम हांफते दिन लगातार भारतीय राजनीति को एक रंगमंच प्रदान करते रहे हैं, जिसमें एक थकी हुई विरासत अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष करती है। भारत की राजनीतिक जमीन इतनी उर्वर है कि विभिन्न आकार एवं प्रभाव वाले परिवार अब भी विशेषाधिकार के रूप में सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं। वंशावली जितनी लंबी होगी, सत्ता का अराष्ट्रीयकरण उतना ही आसान हो जाएगा।

एक प्रांतीय परिवार के चुजूर्ं ने परिवार न होने के लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराते हुए कहा : 'अगर नरेंद्र मोदी का अपना परिवार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उन्होंने मोदी के एक सच्चे हिंदू पुत्र होने पर भी सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बयान लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति की तरफ से आया है, जो बताता है कि भारतीय राजनीति में पारिवारिक मूल्य कैसे काम करते हैं।

लोहिया विचारधारा के पुराने समाजवादी लालू प्रसाद कांग्रेस विरोध की अपनी मूल प्रवृत्ति से काफी दूर हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार को 'बुरे प्रदेश' का पर्यायवाची बना दिया और 'जंगलराज' उनके शासन का आदर्श संस्करण था। और अंत में, वह स्वयं समाजवादी हृदयस्थल की त्रासदी का एक गिरा हुआ पात्र बन गए। उन्होंने कई भूमिकाएं निभाईं, अपने भार के सशक्त चरवाहे से लेकर भारतीय राजनीति के पहले विदूषक तक, जो चुटकुले की चुनावी ताकत को समझते थे। भले ही अंततः चुटकुले भी उन्हीं पर बने। उन्होंने भारत की पहली किचन कैबिनेट के निर्माता की जो भूमिका निभाई, वह पूर्णता लिए थी। जिस चीज ने उनके जीवन को संतुष्ट किया, वह उनके वंश की ताकत थी, जिसको उन्होंने जेल और अन्य जगहों पर भी अपनी विरासत की तरह देखभाल की। वह पितृपुरुष (लालू) आज स्वयं को पारिवारिक मूल्यों के योग्य उपदेशक के रूप में देखते हैं।

यह बात शुरू से ही गलत है कि मोदी का अपना जैविक परिवार नहीं है। यदि लालू प्रसाद का आशय राजनीति में पारिवारिक व्यक्ति के होने से है, तो शायद मोदी अयोग्य हैं, क्योंकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में साझेदार नहीं है। मोदी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया : 'मेरा जीवन खुली किताब है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीय मेरे परिवार हैं। आज इस देश की करोड़ों माताएं एवं बहनें मोदी का परिवार हैं। इस देश का हर गरीब आदमी मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वह मोदी का है और मोदी उनके हैं।'

पारिवारिक मूल्यों को नष्ट करने वाले सिर्फ एक बयान के साथ, जिसे लालू प्रसाद और विपक्ष के उनके ज्यादातर साथी अपने राजनीतिक उद्यम में बढ़ावा देते हैं, मोदी ने परिवार की साख को एक ऐसा अर्थ दिया, जिसे भारत में कोई दूसरा राजनेता दोहराने के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री की पारिवारिक व्यक्ति के रूप में आत्म-छवि हमेशा की तरह उन्हें राजनीति के एक ऐसे दायरे में ले जाती है, जहां परम राष्ट्रवादी के लिए व्यक्तिगत अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। यदि राष्ट्र लोगों की सामूहिक कल्पना है, तो केवल भावनाओं की उच्च खुराक ही इसे तत्काल और अंतरंग अनुभव बना सकती है। यह मोदी के लिए सबसे फायदेमंद भी है।

सत्ता में भारतीय पारिवारिक व्यक्ति का यह आदर्श संस्करण उन्हें उस राजनीतिक संस्कृति से अलग करता है, जिसने 'परिवार पहले' को संस्थागत बना दिया है। इसका सबसे स्पष्ट प्रतिनिधि एक ऐसी भूमिका निभा रहा है, जिसके बारे में उसके अलावा हर कोई जानता है, वह राजनीति में गलती से आ गया है। उसने पहले ही दिखा दिया कि वह राजनीति के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार में से एक ने खुद को मोदी के भारत में निरर्थक बना लिया है। कोई भी आश्वान इस क्षेत्र में राहुल के लिए जगह नहीं बना सकता है, जहां वह लगातार भारत के साथ बेहतर संवाद में असमर्थता या मोदी के खिलाफ तर्क देने पर जोर देते हैं। वह विपक्षी गठबंधन के प्रमुख बने हुए हैं, जो केवल यह दर्शाता है कि मोदी के खिलाफ खड़े सहयोगियों को इस परिवार ने कैसे कहीं नहीं पहुंचने का रास्ता दिखाया है।

मोदी का पारिवारिक मूल्य उस राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देता है, जहां परिवार का मतलब निजी सशक्तीकरण है। हरेक भारतीय को अपने परिवार में शामिल करके उन्होंने अपना परिवार बनाया है, जो 'इंडिया' गठबंधन पर भारी पड़ता है, जो खुद अपनी घटती राष्ट्रीय साख से अवगत है। मोदी ने जो अनकहा छोड़ दिया, वह यह है : सत्ता लोकतंत्र से अर्जित लाभ नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय की साझा संपत्ति है।

आज लोकतंत्र में मोदी को जो सबसे लोकप्रिय राजनेता बनाता है, वह है सत्ता के साथ उनका रिश्ता। पांच साल पहले सत्ता ने उन्हें भारत का सबसे कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार बना दिया था, जिसका ज्यादातर भारतीयों ने अनुमोदन किया। आज वही भारत के लोग, संभवतः उससे भी अधिक स्वयं को मोदी का परिवार के रूप में पहचानते हैं। भारतीय बुजुर्ं (लालू) के पारिवारिक मूल्य इंडिया गठबंधन की वास्तविकता को तेजी से उजागर करते हैं, जो पारिवारिक बोझ के अलावा भी कई बोझों से दबा हुआ है।

edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

जिस तरह भूमध्यसागर अनेक प्रवासियों को लील लेता है, उसी तरह अनेक लोग सहारा रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाते।

आशंकाओं के बीच बेहतर जिंदगी की तलाश

पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर के दूरस्थ शहर अगादेज के बस स्टेशन में लंबे समय बाद हलचल है। हर सप्ताह पश्चिमी और मध्य अफ्रीका से हजारों लोग पिकअप जीपों पर यहां से सहारा रेगिस्तान के लिए निकलते हैं। उत्तर अफ्रीका में कई दिनों के सफर के बाद उनमें से ज्यादातर लोग भूमध्यसागर पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं।

एलायन पेल्टायर

वर्षों तक नाइजर की यूरोप समर्थक सरकारों ने अगादेज सीमा को बंद कर रखा था, ताकि यहां से लोग यूरोपीय देशों की तरफ अवैध तरीके से न जा पाएं। बदले में यूरोपीय संघ नाइजर को वित्तीय मदद देता था। पर पिछली गर्मियों में सैन्य तख्तापलट कर जनरलों ने जब नाइजर की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक मदद बंद कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में नाइजर की सैन्य सरकार ने अगादेज की सीमा खोल दी है, अब इस शहर में यूरोप जाने वालों की संख्या फिर बढ़ने लगी है।

कहते हैं कि अगादेज सीमा से सड़क रास्ते से यूरोप के लिए निकलना अटलांटिक महासागर पार कर यूरोप जाने की तुलना में कर्म खर्चीला और कम खतरनाक है। बताया यह भी जाता है कि इस रास्ते से सैकड़ों वर्षों से व्यापारियों और लोगों की आवाजाही रही है। लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने, उससे पहले उन्हें शरण देने और उन्हें सामान बेचने के काम से अनेक स्थानीय परिवारों की गृहस्थी चलती है। पिछली सरकारों ने इन लोगों में से ज्यादातर को गैरकानूनी गतिविधियां चलाने के जुर्म में जेल में डाल दिया था। लेकिन सैन्य सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है।

लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने, उससे पहले उन्हें शरण देने और उन्हें सामान बेचने के काम से अनेक स्थानीय परिवारों की गृहस्थी चलती है।

इन दिनों अगादेज से रोज सैकड़ों छोटी पिकअप जीप निकलती हैं। हर जीप में तीस लोग ठुंसे रहते हैं। ये जीपें सैन्य सुरक्षा में चलती हैं, ताकि रास्ते में लुटेरे इन्हें निशाना न बना सकें। लेकिन जिस तरह भूमध्यसागर अनेक प्रवासियों को लील लेता है, उसी तरह अनेक लोग सहारा रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाते।

अगादेज की सीमा से निकलने वाला हर अफ्रीकी यूरोप नहीं जाता। उनमें से अनेक लोग उत्तर अफ्रीका के देशों में कुछ साल काम करते हैं, फिर घर लौट जाते हैं। लेकिन उन देशों में भी कई बार प्रवासियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। मसलन, अल्जीरिया में अवैध तरीके से घुसनेवाली महिलाओं को यौन अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद बेहतर जिंदगी की तलाश में लोगों का इस सीमा से जाना जारी है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

वैश्विक निर्यात में हिस्सा

पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वैश्विक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी मात्र 1.8 फीसदी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है।

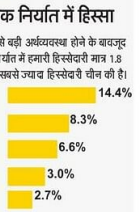

आंकड़े वर्ष 2022 के हैं।

स्रोत : WTO

जो कड़वा सुनकर भी मीठा बोलता है, वही सच्चा संत है। जो निंदा और आलोचना सुनकर क्रोधित नहीं होता, वही सफल गृहस्थ है।

अनूठा वशीकरण मंत्र

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

आध्यात्मिक विभूति पंडित मिहीलाल जी की वाणी इतनी मधुर व प्रभावी थी कि जो कोई उनके पास सत्संग करने के लिए आता, वह उनकी प्रेरणा से समाज सेवा और परोपकार करने लगता। वह अक्सर कहते थे कि जो कड़वा सुनकर भी मीठा बोलता है, वही सच्चा संत है। जो निंदा और आलोचना सुनकर क्रोधित नहीं होता, वही सफल गृहस्थ है।

एक बार मिहीलाल जी टूंडला प्रवास पर थे। एक व्यक्ति उनके सत्संग के लिए आया। उसने किसी से सुन रखा था कि पंडित जी वशीकरण मंत्र जानते हैं। उस व्यक्ति का अपने पड़ोसियों से विवाद था। उसने सोचा कि यदि पंडित जी वशीकरण मंत्र की दीक्षा दे देंगे, तो वह सभी को जीत लेगा। उस श्रद्धालु ने पंडित जी से पूछा, महाराज, क्या आप वशीकरण मंत्र जानते हैं और उसकी जाप-विधि मुझे बता सकते हैं?

पंडित जी ने हामी भरी, तो वह हर्षित हो उठा। पंडित जी ने कहा, भैया, मैं सबसे मीठा बोलता हूं। किसी की बात व्यर्थ में नहीं काटता। धैर्य से सबकी बातें सुनता हूं। हृदय से सबका भला चाहता हूं। यही वशीकरण मंत्र है। तुम इसका पालन करो, यह तुरंत प्रभावी चमत्कार दिखाएगा।

उस जिज्ञासु का समाधान हो गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 जनवरी, 1955

सिंचाई कर विरोधी सभा आयोजित

सिंचाई-कर विरोधी सभा

दिगनेर में कल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक किसान सम्मेलन में बढ़े हुए सिंचाई कर का विरोध किया गया और किसानों से उसे न चुकाने की अपील की गई। किसान हुसमसिंह परिहार की गिरफ्तारी का विरोध किया गया।

दिगनेर में कल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित एक किसान सम्मेलन हुआ। इसमें सर्वश्री पं० भीकुराइच पाठोपाल, हुजराजसिंह, और रामसिंह चौहान के भाषण हुए जिन्होंने बढ़े हुए सिंचाई कर का विरोध किया और किसानों से उसे न

चुनावी मौसम में जरा देखिए बंगाल को

चुनावों की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल में रक्तपात शुरू हो चुका है। ममता को सबसे ज्यादा भरोसा नकदी बांटने वाली सरकारी योजनाओं पर है।

बिमल राय

राजनीति

संदेशखाली मामले पर पूरे देश में शर्मसार बंगाल के चुनावी अखाड़े में आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने *एकला चलो रे* का ही रास्ता अपनाया। ममता की प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं जब-तब पोस्टरों में दिखती रही हैं और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक तो आज भी जनसभाओं में 71 साल की बुआ को पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं। दीदी ने गठबंधन के लिए कांग्रेस की करुण पुकार को अनसुना करते हुए अपने 42 प्रत्याशियों की घोषणा करवा दी। चलिए, मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन की बात को अप्राकृतिक मान लेते हैं, पर उनका उदय तो कांग्रेस से ही हुआ है।

तृणमूल को लगता है कि वह अकेले ही पीएम मोदी का अश्वमेध का घोड़ा बांध लेगी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 5.7 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि 2021 के चुनावों में उसे लगभग तीन प्रतिशत मत मिले। लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 43.7 और भाजपा को 40.6 प्रतिशत वोट मिले थे।

कांग्रेस का पिछला वोट प्रतिशत भले ही मामूली हो, पर राज्य में लंबी उड़ान भरती दिख रही भाजपा को रोकने की कोशिश या प्रयोग वे कर सकती थीं। वामपंथी दल, खासकर सीपीएम का भी अब तक कांग्रेस से कोई चुनावी तालमेल नहीं हो पाया है। वहां भी यही सवाल बाधा बना हुआ है कि वाम वोट तो कांग्रेस को मिल जाते हैं, पर 35 साल तक विपक्ष में रहकर कामरेडों का चाबुक खाने वाले कांग्रेसी अपने घाव नहीं भुला पाते।

हां, मुस्लिमों व दलितों में तेजी से जनाधार बढ़ा रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट और वाम दलों से तालमेल की बात चल रही है। ममता को सबसे ज्यादा भरोसा नकदी बांटने वाली सरकारी योजनाओं पर है। हालांकि संदेशखाली कांड के बाद महिलाओं ने मुखर होकर कहा कि अपनी इज्जत और स्वाभिमान के बदले उन्हें यह राशि नहीं चाहिए। बताया जाता है कि सागरदीघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के बाद क्षेत्र में लक्ष्मी भंडार सुविधा बंद कर दी गई थी और दोबारा यह सुविधा तब चालू हुई, जब वहां से जीते कांग्रेस प्रत्याशी बायरन विश्वास तृणमूल में लौटे। सीएए लागू होने के बाद और घायल होने से पहले ममता ने घुमा-फिराकर मंचों से ही ऐलान किया कि नागरिकता के लिए आवेदन करते ही वे अवैध नागरिक हो जाएंगे और राज्य सरकार की सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।

इधर, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आने पर हर महिला को 3-3 हजार रुपये देने का वादा कर रहे हैं। ममता ने केंद्र की ओर से जनकल्याण की योजनाओं का धन रोक देने को चुनावी मुद्दा बनाया है। हालांकि भाजपा इन योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों को उछाल रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी आरामबाग रैली में साफ कहा कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा। भाजपा पूछ रही है कि बंगाल सरकार अदालत क्यों नहीं जाती? हम दिल्ली चुके हैं कि केंद्र से पावना के मामले पर केरल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट गया और उसे इस मसले का हल मिला।

ममता अपनी दूसरी ताकत बहुचर्चित धर्मनिरपेक्षता को मानती हैं। लेकिन बदले माहौल में यह ताकत कमजोरी के तौर पर देखी जा रही है। संदेशखाली मामले में ईडी टीम पर जानलेवा हमला करवाने वाले शेख शाहजहां को 55 दिन तक पकड़ा नहीं गया, उससे तुष्टीकरण की अवधारणा ही बलवती हुई। वैसे कुछ साल पहले ईद मिलन समारोह में सीएम ममता ने जब मंच से कह दिया कि दुधारू गाय की लात भी सही जाती है, तो इसमें छिपाने लायक कुछ रह नहीं जाता। इसके मुकाबले में राज्य की 70 फीसदी हिंदू आबादी के ध्रुवीकरण की भी संभावना बन सकती है।

इस बीच, चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में रक्तपात शुरू हो चुका है। इस माहौल में एक दिन देश ने यह भी देखा कि घर में गिरकर घायल होने के बाद एक सीएम के माथे से बहता खून सूख जाता है और उनकी पार्टी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसी तस्वीर को सर्कुलेट करती है। ध्यान रहे कि वह तस्वीर अस्पताल की थी और सीएम को घर से एंबुलेंस में नहीं, भतीजे अभिषेक अपनी गाड़ी में लाए। सीएम के घर में थोड़ी-सी रूई, एक बैंडेज और चार बूंद डेटाल का न होना बंगाल की कैसी तस्वीर पेश करता है? मेडिकल बुलेटिन में पीछे से धक्का मारने की थ्योरी भी कम दर्दनाक नहीं है! सहानुभूति लहर की उम्मीद करने वालों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए।

दैनिक जागरण

विनम्रता के आभूषण से व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ता है

चीन की दबंगई का मुकाबला

विजय क्रांति

तिब्बत वीन की दुखती रग है। इस दुखती रग को छेड़कर ही उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है

चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से उकसावे वाला बयान दिया है। उसके रवैये से साफ है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे का इस्तेमाल करते हुए जब अक्साई-चिन को हड़पने का काम किया था, तब प्रधानमंत्री रहे पं. नेहरू ने कड़ी प्रतिक्रिया वाला पत्र चीन सरकार को भेजने का निर्देश दिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही यह कहते हुए पत्र को रुकवा दिया कि चीन से रिश्ते खराब करने के बजाय वह खुद इस सवाल को चीनी प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे, लेकिन कभी यह मुद्दा उठाया नहीं। जब इस भारतीय इलाके में बनी 1200 किमी लंबी सड़क 'जी-219' के उद्घाटन समारोह के लिए चीन सरकार ने पीकिंग (आज का बीजिंग) में भारतीय राजदूत को भी न्योता भेजा, तब भी नेहरू सरकार की मूल आपत्ति बस इस सवाल पर थी कि चीन सरकार के मजदूर भारत से बीजा लिए बिना वहां कैसे गए? अक्साई-चिन का क्षेत्रफल पूरे भूटान देश जितना है। इस पर अपने कब्जे और इसी कारोबारस हाईवे के रास्ते पाकिस्तान से जुड़कर अब चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के लिए स्थायी रूप से गंभीर खतरा पैदा किया हुआ है।

चीन की हेकड़ी और दादागीरी घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने तिब्बत पर जबरन किए गए कब्जे को समय के साथ न केवल बहुत मजबूत कर लिया है, बल्कि तिब्बत को अपनी नई सैन्य छावनी की तरह इस्तेमाल करते हुए वह आए दिन भारत, नेपाल और भूटान के इलाकों पर दावे करता रहता है। तिब्बत को आधार बनाकर चीन ने न केवल 1962 में भारत पर एकाएक हमला बोलकर हजारों वर्ग किमी जमीन हड़प ली, बल्कि तिब्बत की नदियों पर दर्जनों बांध बनाकर वह भारत आने वाले पानी को रोकने और उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करने का अभियान भी चला रहा है। 2002 और 2005 में कम से कम तीन मौकों पर चीन तिब्बत की नदियों के पानी को रोककर और फिर उसे अचानक छोड़कर भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 'वाटर-बम' की तरह इस्तेमाल कर चुका है।

चीन के भारत विरोधी की इस कड़ी में ताजा अध्याय बना है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अरुणाचल में सेला सुरंग मार्ग का उद्घाटन करने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है और इसमें न तो भारत के प्रधानमंत्री को जाने का अधिकार है और न वहां किसी तरह की सड़क, सुरंग या कोई और

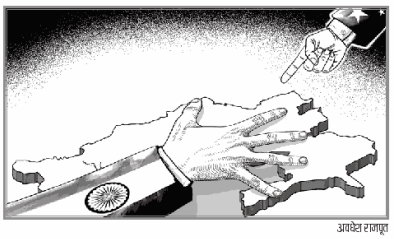

आशुतोष राणापूत

निर्माण करने का अधिकार है। चीन के इस दावे का सबसे हास्यास्पद पक्ष यह है कि वह तिब्बत पर अपने गैरकानूनी और औपनिवेशिक कब्जे पर शर्मिंदा होने के बजाय अरुणाचल को 'दक्षिणी तिब्बत' बताते हुए उसे तिब्बत का और अंततः चीन का हिस्सा मानता है। पिछले वर्ष अगस्त में चीनी गृहमंत्री अमित शाह जब अरुणाचल सीमा के 'प्रथम गांव' किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेज' अभियान की शुरुआत के लिए गए, तब भी बीजिंग सरकार ने हंगामा किया था। इससे पहले अक्टूबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और कई मौकों पर दलाई लामा तथा विदेशी राजदूतों की अरुणाचल यात्रा के दौरान भी चीन अनाप-शनाप बयान देता रहा है। ऐसे भी कई मौके आए हैं, जब चीन में खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले अरुणाचल और जम्मू-कश्मीर के भारतीय खिलाड़ियों को उसने सामान्य वीजा देने के स्थान पर उन्हें नत्थी वीजा जारी किया, क्योंकि वह इन दोनों राज्यों को भारत का हिस्सा नहीं मानता।

भारत सरकार को उकसाने के लिए चीन सरकार सात साल में कम से कम तीन बार अरुणाचल के कई शहरों और कस्बों के चीनी नामों की घोषणा कर चुकी है। यहां तक कि उसने अब अरुणाचल को एक चीनी नाम 'जांगनान' भी दे दिया है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ है 'दक्षिणी तिब्बत।' तिब्बत पर चीन के औपनिवेशिक कब्जे और वहां की जनता के मानवाधिकारों के सवाल पर दुनिया भर में चीन की किरकिरी का असर कम करने के लिए अब वहां की सरकार 'तिब्बत' के बजाय उसके चीनी नाम 'शीजांग' को प्रचारित करने में लगी हुई है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई-चिन तथा कई अन्य क्षेत्रों पर अपना दावा जताने के लिए चीन सरकार ने अगस्त 2023 में नया नक्शा भी जारी कर दिया, जिसे वह चीन का 'मानक' नक्शा बताती है।

चीन की ऐसी प्रत्येक हरकत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय हर बार उसी चिरपरिचित बयान को दोहराता है कि अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चीन के बेतुके दावों से इस जमीनी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि अरुणाचल भारत में ही है। विदेश मंत्रालय का बयान देखने में भले ही तर्कसंगत लगे, लेकिन यह मोदी सरकार की छवि के अनुसार कम और नेहरू युग के जुबानी जमाखर्च जैसा ज्यादा लगता है। भारत की जनता अब यह उम्मीद करने लगी है कि चीनी दादागीरी की प्रभावी काट के लिए नेहरू युग जैसी जुबानी जंग के बजाय मोदी की शैली में कुछ ठोस करना होगा। जिस तरह चीन की नीति युद्ध की अपनी सीमा में लड़ने के बजाय दुश्मन के घर के भीतर ले जाकर लड़ने की है, वैसी ही नीति अब मोदी सरकार को भी अपनानी होगी। उसे इस सच्चाई को ध्यान में रखना होगा कि भारत, नेपाल और भूटान के खिलाफ चीन की असली ताकत उसकी तिब्बत में गैरकानूनी मौजूदगी है।

इसलिए जब तक चीन का तिब्बत पर कब्जा बना रहेगा तब तक दक्षिण एशिया पर उसकी दादागीरी इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसलिए चीन की इस दुखती रग पर प्रहार करके ही उसके अक्खड़पन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश पर 'दक्षिणी तिब्बत' नामकरण के चीनी दावों का सही जवाब यही होगा कि तिब्बत पर उसके गैरकानूनी कब्जे को चुनौती दी जाए। दुनिया में अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई शक्तियां भारत की नीति में इस बदलाव का वर्षों से इंतजार कर रही हैं। चीन के खिलाफ तिब्बत एक ब्रह्मास्त्र जैसा है, जिसे अब तक भारत ने भुलाए रखा है।

(लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

राहुल गांधी की कमजोरी

राहुल गांधी ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वह अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखते। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर प्रहार करने के लिए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम उससे ही लड़ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि वह नरेन्द्र मोदी से पूरी आक्रामकता के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन समझना कठिन है कि सत्ता की शक्ति का मुकाबला करने के लिए उन्हें यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति...। आखिर उन्हें हिंदू धर्म का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? यदि वह शिवभक्त हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो फिर उन्हें इतनी साधारण सी बात तो पता होनी ही चाहिए कि हिंदू धर्म में शक्ति की क्या मान्यता और महत्व है? उन्हें सत्ता की शक्ति और हिंदू धर्म की शक्ति में अंतर करना तो आना ही चाहिए। इस पर आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के अनावश्यक वक्तव्य को लेकर उन पर निशाना साधा। निशाना सही निशाने पर लगा, यह इससे प्रमाणित होता है कि अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता स्पष्टीकरण देने के साथ यह समझाने में लगे हुए हैं कि शक्ति के इतने प्रकार होते हैं और उनके कहने का यह नहीं, वह मतलब था। इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में हिंदू धर्म की शक्ति का उल्लेख करने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता था। यदि उन्हें यह औचित्यपूर्ण लगता है तो क्या वह अन्य पंथों के रूपक का इसी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का साहस दिखाएंगे?

यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने के लिए अर्थ का अनर्थ करने वाला बयान देकर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया हो। राहुल गांधी को तो यह अच्छे से पता होगा कि जब उन्होंने चौकीदार चोर है का जुमला उछाला था, तो भाजपा ने किस तरह उसका उपयोग अपने पक्ष में कर लिया था। इसी तरह उन्हें यह भी स्मरण होना चाहिए था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनका खून की दलाली वाला बयान किस तरह कांग्रेस पर भारी पड़ा था। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति वाला बयान अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर दिया। ऐसा करके उन्होंने यही मौका उपलब्ध कराया कि इस यात्रा के स्थान पर उनके इस बयान की चर्चा हो। यह तो दिख रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार को लेकर दिन-प्रतिदिन और मुखर होते जा रहे हैं, लेकिन वह अपने शब्दों के चयन को लेकर गंभीर नहीं दिखते। यही कारण है कि वह ऐसा कोई बिम्ब नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जिससे देश की जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके।

पर्यटकों का आगमन

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है और लाखों की संख्या में लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। सर्दी में पर्यटन कारोबार में मंदी के बाद मौसम में बदलाव आने के बाद अब सप्ताहांत में पर्यटकों का प्रदेश के प्रमुख पर्यटनस्थलों पर आगमन सुखद है। इससे पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह का संचार हुआ है। रविवार को पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात शिमला के होटलों में आक्यूपेंसी 50 प्रतिशत तक पहुंच गई। मनाली में 60 प्रतिशत तक होटलों के कमरे भरे हैं। रविवार को ही कुल्लू जिले में करीब 2000 पर्यटन वाहन पहुंचे। कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज एवं चंबा जिले के डलहौजी में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रदेशभर में इन दिनों मेलों का क्रम शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को भी संबल मिला है। मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न हो गया है जबकि ऊना जिले के मैड़ी में होला मोहल्ला मेला और दियोटसिद्ध में बाबा बालक नाथ मंदिर में चैत्र मेले शुरू हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों में चैत्र मेले भी जल्द शुरू होने वाले हैं। पर्यटन व्यवसाय कमाऊपूत बन सके, इसके लिए व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने की दिशा में भी प्रयास करने होंगे। सड़कों की दशा ठीक करनी होगी। पर्यटकों से मनमाने दाम वसूलने से भी बचना होगा। फर्जी टूरिस्ट गाइड्स पर अंकुश लगाना होगा। यातायात बाधित होने की सूरत न आए, इसके लिए भी कदम उठें, यह समय की मांग है। पर्यटक प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को चाहिए कि यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं देने के साथ बेहतर व्यवस्था करें ताकि पर्यटक यहां बार-बार आना चाहें।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आना सुखद है, लेकिन उन्हें सहेजे रखने के लिए जरूरी व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी

देश को नई दिशा देने वाला चुनाव

शशांक मणि

यह जनादेश ऐसा भारत बनाएगा, जो अपने मूल्यों, संस्कृति और जन की ऊर्जा से संचालित होगा

मध्यवर्ग के लिए उत्सव जैसा चुनाव। फाइल

इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के आह्वान पर एक जनमत संग्रह के तौर पर भी देखे जाएंगे। आजादी के अमृतकाल में हो रहे आम चुनाव देश के उभरते मध्यवर्ग के लिए एक उत्सव सरीखे भी हैं, जिसे इन दिनों मिडिल आफ डायमंड इंडिया (एमओडीआइ-मोदी) कहा जा रहा है। यह 80 करोड़ से अधिक मजबूत वर्ग ना तो बहुत अमीर है और न ही बहुत गरीब है। यह वर्ग अमृतकाल में 2047 तक विकसित भारत के मिशन में सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह यह चुनाव अनूठा है, क्योंकि यह मतदाताओं को अगले 25 साल के प्रयास का समर्थन करने की चुनौती देता है, जिसके परिणाम देखने के लिए कई लोग तो शायद जीवित भी न रहें। विकसित भारत सभी अवश्य देखना चाहते हैं। यह एक असाधारण प्रगति का आह्वान है, जो ऐसे भारत का निर्माण करेगा, जो अपने मूल्यों, संस्कृति और 140 करोड़ लोगों की गगनचुंबी ऊर्जा से संचालित होगा। यह ऐसे विकास की भी चर्चा करता है, जो देश की विशाल मानव आबादी के साथ-साथ हमारी संस्कृति और प्रकृति के साथ मेल खाता है। इसमें नागरिकों, सरकारों और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास के माध्यम से एक विकसित भारत बनाने की क्षमता है, जिसे प्रधानमंत्री जनभागीदारी कहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार बढ़ाना विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इस वृद्धि को आकार देने की प्रक्रिया में लाखों लोगों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा। यह हमारे गणतंत्र को फिर से परिभाषित करते हुए लाखों नागरिकों के जीवन का संचालन करेगा। विकसित भारत के लक्ष्य को राष्ट्रीय मिशन बनाना कठिन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में तीन ऐसे परीक्षण किए हैं, जिनकी परिणति देखकर इसकी सफलता की आस जगती है। उनके पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन का परीक्षण किया गया, जो केवल कुछ टेकनोक्रेट पर नहीं, बल्कि देश भर के विभिन्न वर्गों को शामिल करने पर आधारित है। दूसरा हालिया प्रयास जो अभी भी चल रहा है, वह है जल जीवन मिशन। इसका असर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में देखता हूं। आजादी के 77 साल के इंतजार के बाद आज मेरे गांव के सामान्य घरों को पीने योग्य पानी मिल रहा है। तीसरा सांस्कृतिक परीक्षण अयोध्या में श्रीरामलला के मंदिर का बाट्टा पूरा करना है। इसने कई छुपी कहानियों, गौरव और संभावनाओं को उभार दिया है। श्रीराम मंदिर की कहानी की तरह देश भर में और भी छुपी हुई कहानियां सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि विरासत को विकास के साथ जाना होगा। अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने का लक्ष्य इसका प्रमुख संकेत है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा समर्थक मध्यवर्ग है। जाति, वर्ग और पंथ से परे एक स्थिर सरकार बनाने के लिए इस बड़े वर्ग का वोट मायने रखता है, लेकिन नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से अमृतकाल के वादे को पूरा करना और भी अधिक आवश्यक है।

विकासशील भारत को केवल भौतिक सुख से नहीं मापा जा सकता। यह एक अमेरिकी सभ्यता की महज नकल करना होगा। अमृतकाल नागरिकों को पंच प्रण के माध्यम से जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की बात करता है, जिसके लिए नागरिक शपथ भी ले रहे हैं। मोदी का प्रभाव केवल एक बड़े वर्ग में ही नहीं है, बल्कि वह उस जनसमूह को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके लिए वह एक अलग विकासात्मक माडल तैयार करते दिख रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से अमेरिका या राज्य केंद्रित चीन द्वारा चुने गए रास्ते से अलग मार्ग है। कई सेक्टरों से जूझ रही दुनिया में मिडिल आफ डायमंड इंडिया अन्य उभरते देशों को अपना केंद्र खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। पिछले साल जी-20 की सफल अध्यक्षता ने इस नेतृत्व का संकेत तब दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा।

विरासत को साथ लेकर दीर्घकालिक विकास का मार्ग 1857 में ही शुरू हो गया था, जब हमारे नेताओं ने भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इसका आरंभ मंगल पांडे द्वारा चलाई गई गोली और झांसी में बीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की तलवारों की चमक से हुआ था। साहस के इस प्रदर्शन और उनके बलिदान ने स्वामी विवेकानंद, बालगंगाधर तिलक, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के लिए 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। यह सच है कि व्यक्तिगत स्वराज मिलने में देरी हुई, क्योंकि समाजवाद ने एक गतिहीन राज्य का निर्माण किया और वंशवादी राजनीति ने सामान्य प्रतिभा के वास्तविक उत्थान को रोक दिया। तब हमारी शासन की प्रवृत्ति दूरदर्शी नहीं थी, जब आत्मनिर्भरता लाखों लोगों को ऊर्जावान बना सकती थी।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित होकर भाजपा ने आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयास किया, जो अब मध्यवर्गीय भारत को स्वयं की ऊर्जा से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे रहा है। पीएम मोदी ने दस साल देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सरकार को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें डिजिटल तकनीक का उपयोग करना और नागरिक केंद्रित होना महत्वपूर्ण था। अब देश एक नई छलांग के लिए तैयार है। यह न केवल जीडीपी में वृद्धि करेगा, बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण के अनुरूप लोगों की मानवीय क्षमता का भी विकास करेगा।

(स्तंभकार मिडिल आफ डायमंड इंडिया (एमओडीआइ): नेशनल रेनेसां ब्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइज के लेखक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

घर-परिवार

हंसते-खेलते एवं सुखी घर-परिवार में धरती का स्वर्ग देखने को मिलता है और दुखी परिवार में नरक। पारिवारिक जीवन ऐसा होता है कि उसे स्वर्ग के समान आनंद देने वाली परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है और नरक के समान कष्ट देने वाली परिस्थितियों में भी ढाला जा सकता है। घर के सदस्य अपने आपसी व्यवहार से चाहें तो घर में प्यार, खुशियों एवं अपनत्व की गंगा बहा सकते हैं और चाहें तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का गंदा नाला भी बहा सकते हैं।

परिवार अपने सदस्यों को बांधकर रखता है। परिवार में अच्छे संस्कार उसके सदस्यों को सही राह पर ले जाते हैं। उन्हें आदर्शवादी बनाते हैं। संस्कारी परिवार के निश्चित अनुशासन-नियम होते हैं, जो उसके सदस्यों को बहकने-भटकने नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। परिवार की स्वस्थ परंपराएं और रीति-रिवाज सदस्यों की शुभता का ध्यान रखते हैं। उनका संवर्द्धन करते हैं। वहीं, यदि कोई परिवार नियमों एवं अनुशासनों को नहीं माने, बल्कि इन्हें बंधन कहता हो, अच्छे संस्कारों को ढोंग कहता हो, परिवार के सदस्य अपनेपन का व्यवहार नहीं करते हों, अपना दायित्व नहीं निभाएं, बल्कि दूसरों के अधिकारों को छीनने की बात करते हों तो ऐसे घर-परिवार में नरक का वास हो जाता है।

जिस घर में नित्य लड़ाई-झगड़े होते हैं, जिस परिवार के सदस्य एक-दूसरे को समझना नहीं चाहते, दूसरों के कष्ट, पीड़ा, दुख देने में अच्छा लगता है, वहां सुख का निवास हो ही नहीं सकता। ऐसे परिवार में किसी को एक पल की भी शांति नहीं मिलती। हंसी-खुशी भरा परिवार कुछ अलग होता है। ऐसे घर में सभी एक-दूसरे का सम्मान एवं प्यार करते हैं। दुख के समय सभी एक-दूसरे का साथ देते हैं। कहीं किसी को यह प्रतीत नहीं होता कि वह अकेला है, बल्कि उसे यही लगता है कि उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं।

नीता देवी

चुनावी चर्चा का हिस्सा बने पर्यावरण

देवेंद्रराज सुथार

पिछले कुछ दशकों से वाहन चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन रहे हैं। चुनाव अभियानों की बढ़ती लागत में इन वाहनों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए हजारों वाहनों का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में एसयूवी कारें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बन गई हैं।

यदि एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 30 दिनों के लिए चुनाव संबंधी कार्यों के लिए एक हजार वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक वाहन प्रतिदिन लगभग 15 लीटर जीवाश्म ईंधन की खपत करता है तो पूरे भारत में कुल चुनाव अभियान में लगभग 244 मिलियन लीटर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होगा। अगर डीजल का उपयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश में कुल मिलाकर अगले कुछ हफ्तों में लगभग 660 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाईआक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होगी। एक लीटर डीजल लगभग 2.7 किलोग्राम कार्बन डाईआक्साइड वायुमंडल में छोड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक और फ्लेक्स बैनरों का बड़े पैमाने पर उपयोग इस समस्या को और भी जटिल बना देता है। प्रतिबंधों के बावजूद ये सामग्रियां खूब इस्तेमाल हो रही हैं और निर्माण से लेकर निपटान तक पर्यापत मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रही हैं। यदि ऐसे बैनरों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन किया जाए तो यह भी एक चिंताजनक आंकड़ा दिखाएगा।

पर्यावरण को चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ शासन में भी जिम्मेदारी की भावना आएगी

हमें निश्चित रूप से भारत में चुनाव अभियान के लिए एक बेहतर, अधिक जलवायु-अनुकूल तरीका खोजने की आवश्यकता है। पर्यावरण अनुकूल चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग को पहल करनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध और नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के बेड़े में तीन से अधिक कारें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के कुल कार्बन फुटप्रिंट को मापने के लिए एक नियम बनाना चाहिए। प्रति उम्मीदवार अनुमत कुल व्यय पर निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार इसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए। यदि यह डाटा सार्वजनिक किया जाता है तो यह उम्मीदवारों को हरित उपाय अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। इस तरह के प्रयास से नागरिकों को भी संबंधित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के कुल कार्बन फुटप्रिंट को जानने का अवसर मिलेगा। पर्यावरणीय चेतना को चुनावी चर्चा की हिस्सा बनाने से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि इससे शासन के स्तर पर भी एक जिम्मेदारी की भावना कायम होगी। हालांकि यह काम कठिन है, लेकिन असंभव नहीं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

लोकतंत्र की मर्यादा का रखें ध्यान

'महासमर का मौजूदा परिदृश्य' शीर्षक से प्रकाशित राजकुमार सिंह का आलेख पढ़ा। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में आम चुनाव की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन्हें समर्थन करने वाले दूसरे राजनीतिक दल भी वोट बैंक बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चुनावी रैलियां हो रही है, लेकिन रैलियों से आमजन को कोई परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। चुनाव के समय नेता एक-दूसरे की गलत नीतियों की आलोचना करने के बजाय कई बार निजी जीवन पर भी हमले करने लगते हैं। कई बार तो कुछ राजनेता या उनके समर्थक ऐसी कड़वी जुबान बोल देते हैं जो आम जनता को भी नागवार गुजरती है। निजी हमले से देश की कोई भी समस्या हल तो नहीं होने वाली, बल्कि इससे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनता है। अगर आलोचना करनी हो तो वह सामने वाली की गलत नीतियों की करें, ताकि देश के लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी देशभर में लग गई है। इसका राजनीतिक दलों और नेताओं को पालन करना चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और उचित तरीकों से हो सकें। युवाओं को चाहिए कि वे आम लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक करने के लिए काम करें, न कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें।

सुरेशन कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

जल संकट की आहट

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आजकल जल संकट से जूझ रही है। इसे देखते हुए कुछ संस्थाओं ने जल बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना घोषित कर दिया है। बेंगलुरु ही नहीं दुनिया के और भी बहुत से शहर जल संकट का सामना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में तो पिछले छह वर्षों से जल राशन की तरह मिल रहा है। कुछ समय पहले नीति आयोग ने कहा था कि हमारे देश में 2030 तक 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का साफ जल उपलब्ध नहीं होगा, काफी चिंताजनक है। भारत में जहां एक तरफ गर्मियों में सूखा पड़ता है तो वहीं बरसात के दिनों में कुछ राज्य बाढ़ की चपेट में भी आ जाते हैं। अगर सरकारें और प्रशासन बरसाती पानी को संभालने के लिए कुछ उपाय करें तो यह गिरते भूजल स्तर को कुछ हद तक रोक सकता है। जल संकट का मुख्य कारण इसका बेहिसाब दोहन है। प्रकृति का दोहन बंद होगा तो समय पर बारिश होगी। अगर समय पर और उचित मात्रा में बारिश होगी तो यह देश को जल संकट से बचाने में मददगार साबित होगा। जल के साथ प्रकृति बचाना भी हम सबका नैतिक कर्तव्य है।

raju09023693142@gmail.com

वास्तविकता से साक्षात्कार

'नागरिकता कानून पर दुष्प्रचार' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में संजय गुप्त ने उन नेताओं को वास्तविकता से साक्षात्कार कराया है, जो एक ऐसे देश के अल्पसंख्यकों को लेकर दिन-रात फिक्रमंद नजर आते हैं, जो स्वाधीनता बाद तमाम सरकारों में संविधान प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपभोग ही नहीं करते आ रहे, बल्कि उनकी आबादी में खासी बढ़ोतरी उनकी बेहतरी की कहानी बयां करती है। जबकि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक दुर्दशाग्रस्त जीवन जीने को अभिशप्त हैं। वोट बैंक के फेर में पड़ कर पंथनिरपेक्षता के नाम पर ये नेता सेम्प्रदायिक राजनीतिक करने नजर आते हैं। सीएए किसी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी को नया आमंत्रण नहीं है, बल्कि 2014 के पहले आए हुए शरणार्थियों के लिए है। फिर वे मतदाता के सिवाय भारतीय संसाधन बन लंबे समय से उपभोग कर ही रहे हैं। ऐसे संसाधनों का उपभोग न जाने कितने घुसपैठिए कर रहे हैं?

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए; नीतेन्द्र डीवाटया द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नईदिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

आजकल

रक्षा क्षेत्र में चुनौती प्रस्तुत करता चीन

वर्तमान में चीन रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे वह इस क्षेत्र में विश्व के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। बात चाहे दक्षिण चीन सागर की हो या हिंद महासागर की, ताइवान का मसला हो या भारत एवं अमेरिका से निरंतर जारी तनाव का, चीन इन सभी मामलों में किसी की नहीं सुन रहा है और लगातार अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी प्रयास में चीन ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है

दक्षिण चीन सागर में 'उच्च सैन्यीकृत कृत्रिम द्वीप' के निर्माण से चीन इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है जो इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। फाइल

वर्ष 2024 के लिए चीन ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगला रक्षा बजट 232 अरब डालर कर दिया है। चीनी रक्षा बजट की यह वृद्धि बीते पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है। चीन का रक्षा बजट ऐसे समय बढ़ाया गया है, जब उसकी अर्थव्यवस्था काफी बुरे दौर से गुजर रही है। चीन इससे पहले भी आर्थिक संकट से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग एक परेशानी वाले काल से गुजर रहे हैं। पिछले साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत थी, जबकि इस साल इसके 4.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ में एक लंबे समय तक वहां की प्रापर्टी सेक्टर की विशेष भूमिका रही है, लेकिन इधर काफी समय से प्रापर्टी सेक्टर की कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और सरकार इनको उबारने के मूड में नहीं है। पहले आर्थिक ग्रोथ कम होने पर चीनी सरकार निर्यात बढ़ाती थी और सरकारी मदद दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। फिलहाल चीन सरकार ने इस साल के लिए पांच प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है जो उसके मानक के हिसाब से कम है। दूसरी तरफ साल 2024 के लिए चीन का रक्षा बजट पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक है। ऐसे में चीन के द्वारा की गई रक्षा बजट की वृद्धि उसके सैन्य इरादों को स्पष्ट करती है।

चीन ने अपने वित्त मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है कि वह दुनिया में अमेरिका के बाद रक्षा बजट पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दूसरा देश है। चीन की विधायिका की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में पांच मार्च को आधिकारिक रक्षा बजट के आंकड़े की घोषणा की गई। अनेक विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि यह धनराशि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए खर्च का केवल एक अंश है। 232 अरब डालर का चीनी रक्षा बजट भारतीय रुपयों में 19.23 लाख करोड़ रुपयों से अधिक है। चीन की तुलना में भारत का 2024-25 के लिए घोषित रक्षा बजट 621541 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से तीन गुना से भी ज्यादा है।

बीते वर्षों की तरफ ध्यान दें तो वर्ष 2023 में भी चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2 प्रतिशत बढ़ाया था। इससे चीन का रक्षा बजट बढ़कर 225 अरब डालर तक हो गया था। वर्ष 2022 में चीन ने अपना रक्षा बजट 7.1 प्रतिशत बढ़ाया था। वर्ष 2020 में चीन का रक्षा बजट 6.6 प्रतिशत बढ़ाया गया था, जबकि वर्ष 2021 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। चीन अपने रक्षा बजट में पिछले नौ वर्षों से निरंतर वृद्धि कर रहा है। उसकी योजना यह है कि वह अपनी सेना को विश्व की नंबर एक सेना बना दे। इसीलिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के कार्यकाल में रक्षा बजट में भारी वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2013 में चीन का रक्षा बजट 8.45 लाख करोड़ डालर था जो अब बढ़कर 19.61 लाख करोड़ डालर तक पहुंच गया है। वस्तुतः शी चिनफिंग ने अपनी सेना को वर्ष 2027 तक विश्वस्तरीय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनका यह भी इरादा है कि चीनी सेना को वर्ष 2035 तक पूरी तरह से अत्याधुनिक बना दिया जाए। इसी वजह से चीन अपना रक्षा बजट निरंतर बढ़ा रहा है।

शी चिनफिंग अपनी चीनी सेना को इतनी आधुनिक बनाना चाहते हैं कि उनकी सेना संसार के किसी छोर पर या किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल कर सके। राष्ट्रपति शी चिनफिंग यह नहीं चाहते हैं कि उनके सैनिकों को युद्ध लड़ने में अधिक मेहनत करनी पड़े। इसीलिए चीन अत्याधुनिक हथियार, मजबूत थियेटर कमांड, स्टील्थ तकनीक व लड़ाकू तकनीक के क्षेत्र में अधिक पैसा लगा रहा है। इनके विकास के बाद युद्ध में विजय दिलाने का काम लड़ाकू जेट विमान, आटोनामस हथियार व अत्याधुनिक मिसाइलें कर देंगी। हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े सैन्य सुधार किए हैं। इन सुधारों के तहत उसने दूसरे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए नौसेना और वायुसेना को प्राथमिकता देते हुए उनका विस्तार किया।

चीन का ध्यान स्टील्थ लड़ाकू विमान, विमानवाहक पोत, सेटेलाइटरोधी मिसाइल समेत नई सैन्य क्षमता विकसित करने पर है। चीन अपना दबदबा बढ़ाने के लिए नौसेना की पहुंच को समुद्री क्षेत्रों में फैला रहा है। इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर नौसेना के विकास पर रहेगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। इस तरह यह स्पष्ट है कि चीन सैन्य क्षेत्र में विश्व के शक्तिशाली देशों की तुलना में सबसे ऊपर रहना चाहता है।

चीन अपनी इसी रक्षा नीति पर चलते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन रहा है। बिगत दो-तीन वर्षों में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल की गई हैं, उतने शायद अमेरिका की नौसेना में न हों। इतने हथियारों की वृद्धि के बाद भी उसकी भूख कम नहीं हुई है। बिटिए हो कि कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपनी नौसेना को संसार की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे चीन पूरा करने में लगा हुआ है। चीन की रक्षा ताकत बढ़ाने वाली यह नीति आने वाले समय में विश्व को नए युद्ध में धकेलने में देर नहीं लगाएगी। इन योजनाओं के पीछे कारण यही है कि चीन का अमेरिका, ताइवान, जापान व भारत के साथ जारी तनाव और हिंद महासागर व दक्षिण चीन सागर में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में उसका सैन्य पक्ष कमजोर न पड़े।

समुद्री क्षेत्र में सामरिक शक्ति का प्रदर्शन

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

रूस-यूक्रेन युद्ध और फलस्तीन-इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है। इन परिस्थितियों के बीच वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने संजोये चीन की अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति के कारण समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है। वाशिंगटन स्थित एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव (एमटीआई) के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दक्षिण चीन सागर के प्रमुख हिस्सों के आसपास चीनी नौसेना के जहाजों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महासागरों में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच चीन ने अपनी उपस्थिति बढ़ाना जारी रखा तथा फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मिसचीफ रीफ को तीन दशकों से नियंत्रित कर इसे 'उच्च सैन्यीकृत कृत्रिम द्वीप' में बदल दिया।

समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से चीन अपने निकट के सागरों व महासागरों को नियंत्रित करने में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित किसी भी क्षेत्रीय युद्ध को लड़कर जीत सकने की है। चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाएं भारत सहित अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। इसी प्रकार पूर्वी एशिया से दूर राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर कब्जा करने की साजिश में लगा हुआ है, जो शांति एवं स्थिरता को भंग करने के साथ ही लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक विकास को कमजोर करने वाली है।

वस्तुतः चीन का आर्थिक उत्थान, सैन्य आधुनिकीकरण और नौसेना में बढ़ता निवेश महासागरीय देशों के हितों को प्रभावित के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक उपलब्धता वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य करता है। तीन लाख करोड़ डालर से अधिक का वार्षिक व्यापारिक मार्ग होने के कारण दक्षिण चीन सागर आज एक के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के साथ ही चीन सुदूर समुद्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बाधित करने की साजिश में लगा हुआ है। समुद्री क्षेत्रों में विस्तार के लिए चीन की बढ़ती उपस्थिति, मुखर व्यवहार और दावे चीन के पड़ोसियों और यहां तक कि इसके तटों से दूर कुछ देशों के बीच प्रतिक्रिया को भड़का रहे हैं। हालांकि ये तनाव अब तक नियंत्रण में रहे हैं, परंतु संघर्ष की आशंका भी बनी हुई है, जो वैश्विक चिंता के रूप में उभरी है।

चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए महासागरीय देशों को एकजुट रहने के साथ ही वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता है। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व अमेरिका द्वारा पसाणु संचालित पनडुब्बी कार्यक्रम भू-राजनीतिक और सैन्य विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीआरआइ के विकल्प जैसे जापान के 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कारिडोर' और भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक कारिडोर (आइएमईसी), यूरोपीय संघ का 'ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट' को अपनाया जाना चाहिए। वस्तुतः भारत और जापान बहु-ध्रुवीय एशिया की केंद्रीय शक्तियां हैं और दोनों देश स्वतंत्र, पारदर्शिता और नियम-आधारित व्यवस्था की पक्षधर हैं, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा है। वर्तमान में संपूर्ण हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र अशांत है। चीनी नौसेना की बढ़ती शक्ति एवं समुद्री पहुंच से उत्पन्न वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियां समुद्र में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रही हैं। संभावित संघर्ष की आशंकाओं से भरे महासागर में चीन को नियंत्रित करने के सामूहिक प्रयास से ही वैश्विक शांति एवं सुरक्षा की आशा की जा सकती है।

खरी-खरी

अब चुप नहीं रहूंगा...

पूरन सरमा

रहीम दास जी की बात मानकर मैं साढ़े चार साल से चुप था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चुप बैठना घाटे का सौदा है। मेरा जैसा बिरौलिया यदि अब चुप रहा तो हाथ खाली रह जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।

बहुत सोच-विचार करने के बाद जब मैं अपने चहेते नेताजी के दरवाजे पर पहुंचा तो भीड़ काफी थी। मुझे एक जानकार की शक्ल दिखाई दी। मैंने कहा, 'भाई साहब इधर हूं।' भीड़ को चीरते हुए वह मेरे पास आ गए। मुझे एक सुनसान पेड़ के नीचे ले गए और बोले, 'ऐसा करो, जबकि तो अपना हुलिया बदलो। ठीक समय पर आए हो। कुर्ता-पायजामा धारण करके मेरे पास परसों आओ। मैं मुखिया जी से मिलवा दूंगा। इस समय तुम्हारे जैसे लोगों की परम आवश्यकता है। हम दो टर्म पूरा करने जा रहे हैं, तीसरे के लिए प्रयत्नशील हैं। खजाना खुला छोड़ दिया है। सब्सिडी आधार कार्ड के आधार पर सीधे आम आदमी के बैंक खाते में दे रहे हैं। इसलिए हमने पासे तो एक से एक नायाब फेंके हैं। सवाल उनका जन सामान्य के दिमाग में बैठाने का है। मुझे विश्वास है तुम्हारा जैसा कार्यकर्ता ही यह कर सकता है।'

मैं बोला, 'सर, आपको तो महंगाई ने मारा है। डीजल, पैट्रोल और गैस के महंगे होने से बाजार की हर चीज आसमान छू रही है।' वे मेरे इस बात को सुनते ही भड़क उठे और बोले, 'गीदी मारो इमेज को। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। तुम को इस बीड़ से अलग मैं क्या झख मारने लाया हूं। इसी में तो करिश्मा करना है।' मैं बोला, 'नहीं सर, मैंने तो बस एक बात कही थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा और अपना आलाप इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि टर्म पर टर्म मिलते जाएंगे।'

वे बहुत खुश हुए। चुपचाप मेरी जेब में कुछ डाल दिया कि वह भारी महसूस होने लगा। बोले, 'जाओ परसों आना और सुनो यह बोलने का वक्त है। झूठ का कारोबार करते हैं हम सब।' मैंने घर पहुंच कर जब अपनी जेब देखी तो गांधी छाप कागज देखकर मैं और पत्नी फूले नहीं समाये। पत्नी ने भी यही कहा, 'अब चुप मत बैठना।' तब से मैं बोले ही जा रहा हूं।

एक्स पोस्ट

बेंगलुरु की घटना यही बताती है कि इस देश में आप सड़क पर नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी दुकान में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते। कुछ लोगों की नजर में यही 'सेक्युलर इंडिया' है।
ऋतिका चंद्रोल @RitikaChandola

राहुल गांधी अपने भाषणों से मोदी की मदद ही करते हैं। बिना पूरी जानकारी के उन्हें हिंदू धर्म में शक्ति के प्रसंग को छेड़ने की क्या आवश्यकता थी?
तवलीन सिंह@tavleen_singh

राहुल गांधी की वजह से हम कभी अच्छा विपक्ष नहीं देख पाएंगे। पता नहीं उनके भाषण कौन लिख रहा है? यही कह देते कि 'हिंदी में शक्ति शब्द है' तो क्या चला जाता? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द इस्तेमाल कर लिया और फिर उसके बाद वही विक्रम-वेताल की कहानी-तू बोला और मैं चला। नवीन चौधरी@naveen1003

मल्लिकार्जुन खरगे को यदि सुरक्षा के लिए सात चरणों के चुनाव से विकास रुक जाने की चिंता है तो कोविन्द समिति की एक साथ चुनाव कराने की राय का विरोध क्यों करते हैं? बंगाल, बिहार, केरल और कश्मीर के अपने साथियों से कहते क्यों नहीं कि हिंसा न करें? चित भी मेरी और पट भी मेरी? शिव कांत@shivkant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

इतने चुनावों-परीक्षाओं के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश बची है?

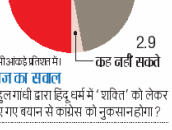

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म में 'शक्ति' को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

यात्राएं करके हुए राहुल जी 'मेच्योर',
सभी समर्थक हो गए अब तो उनके श्योर।
अब तो उनके श्योर रचेंगी मुझ की चक्की,
कांग्रेस सरकार बनेगी अब तो पक्की!
अच्छा हो गी है सोच-सोच कर मन बहलाएं,
करनी हो गी किंतु अभी ढेरों यात्राएं!!
- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचने से रोककर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। साथ ही नगर निकाय, पंचायत और विधानसभा व लोकसभा उपचुनावों में भी तृणमूल का परचम बुलंद रहा, परंतु इस विजय अभियानों के तीन वर्षों के भीतर भ्रष्टाचार, घोटालों, संदेशखाली कांड जैसे मुद्दों से घिरे होने और पार्टी में आंतरिक द्वंद्व चलने के बावजूद ममता ने विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइ से अलग होकर अकेले ही भाजपा से मुकाबला करने के लिए चुनावी रण में उतरकर बड़ा दांव खेला है।

आइएनडीआइए में शामिल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर ममता इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, परंतु गत 10 मार्च को ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित

बंगाल डायरी

चुनावी रण में ममता का बड़ा दांव

रैली में बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही साफ हो गया कि ममता अकेले ही प्रदेश में भाजपा से लड़ेंगी। उधर, राज्य में 35 से अधिक सीटें जीतने के लिए भगवा ब्रिगेड पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में 2019 में भाजपा से हारी हुई सीटों को फिर से हासिल करने की राह तृणमूल के लिए आसान नहीं होगी। वहीं, अपनी जीती 22 सीटों पर भी कब्जा बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। तृणमूल सुप्रीमो के इस दांव का उद्देश्य न केवल भाजपा की सीटों की संख्या को कम करना है, बल्कि अपने संसदीय प्रतिनिधित्व को अधिकतम करना भी है। साथ ही, संभावित विपक्षी गठबंधन सरकार में अपने मोल-भाव की शक्ति को बढ़ाना और सत्ता में भाजपा की लगातार तीसरी बार संभावित जीत का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना भी है। हालांकि ममता के लिए यह दांव 'शेर की सवारी' करने जैसा है, क्योंकि अगर हार हुई तो उनके पार्टी नेताओं

कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 10 मार्च को रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल

में 2019 की तरह दलबदल की लहर पैदा हो सकती है और 2011 से निरंतर राज्य की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर अगर अधिक सीटें जीत जाती हैं तो ममता उन नेताओं की श्रेणी में आ जाएंगी, जो अपने क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को दो बार रोकने में सफल हुई हैं। इसके बाद ममता राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित हो जाएंगी।

दरअसल, 2019 में तृणमूल ने 22 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 18 सीटें मिली थीं। इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि 2021 में बंगाल में परिवर्तन की हवा तेज हो गई थी, लेकिन भाजपा की कुछ रणनीतिक गलतियों और कोरोना महामारी ने तृणमूल की मदद कर दी। ममता के लिए इस बार चुनौती दोतरफा है। पहला, पीएम मोदी ने बंगाल में पिछले कुछ दिनों में चार रैलियां कर भाजपा को चुनौती के रूप में तृणमूल के दरबाजे पर खड़ा कर दिया है। इसे उन्हें रोकना होगा। दूसरा, राज्य में आइएनडीआइए से बाहर निकलने के बाद ममता को यह साबित करना होगा कि वह अपने दम पर भाजपा के बढ़ते कदम रोक सकती हैं। तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, 'हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में भाजपा को हराना है, खासकर उस स्थिति में जब विपक्षी वामदल, कांग्रेस और भाजपा के बीच गुप्त समझौते हैं।' तृणमूल नेताओं का दावा है, 'हमारी ही एकमात्र पार्टी है, जो बंगाल में भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। तृणमूल ही है, जिसके पास बंगाल में भाजपा को हराने के लिए संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व का करिश्मा दोनों है। हमने 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐसा किया था और उस उपलब्धि को फिर दोहराएंगे।'

कई तृणमूल नेता ऐसे हैं, जो मान रहे हैं कि पार्टी में बाहरी चुनौतियों के साथ आंतरिक कलह भी है, जिसने राजनीतिक परिदृश्य को उथल-पुथल कर रखा है। पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आ गई है। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के एक वर्ग और पार्टी के युवा नेताओं के बीच दरार पहले से ही चौड़ी है। ऐसे में एकजुट होकर लड़ना वास्तव में चुनौती है। लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष सामने आया है। टिकट के इच्छुक उम्मीदवार पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को लेकर खुलेआम अर्संतोष जता रहे हैं। अगर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो स्थिति भाजपा के लिए उतनी मुश्किल नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने संशोधित नागरिकता कानून समर्थक होने के रुख का लाभ उठाते हुए बंगाल में 18 सीटें हासिल की थीं, जो तृणमूल से चार कम थीं। इस बार तो उन्होंने सौएपे लागू कर दिया है।

वर्ष 2021 में तृणमूल ने 'बंगाली अस्मिता' पर जोर देकर, उप-राष्ट्रवाद और भाजपा की बाहरी पार्टी वाला नारा बुलंद कर, भाजपा की पहचान की राजनीति का मुकाबला करने के साथ 213 सीटों के साथ लगातार तीसरी जीत हासिल की थी। राज्य में भाजपा के प्रभाव विस्तार के बावजूद विभिन्न चुनावों में तृणमूल का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2019 में 2014 की 34 सीटों की तुलना में 22 लोकसभा सीटें हासिल करने के बावजूद तृणमूल का वोट प्रतिशत 39.8 से बढ़कर 43.3 हो गया था। इसी तरह 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में वोट प्रतिशत 38.93 से बढ़कर 44.91 हो गया। यह 2021 के राज्य चुनावों में अपने चरम पर 48.02 प्रतिशत हो गया, परंतु 2024 में जो पहले की तुलना में तृणमूल के लिए स्थिति विपरीत है।

मंथन

देश के लिए बदलाव का दशक

जिस विरासत और विकास के विमर्श की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें देश के तमाम भौगोलिक क्षेत्र पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शामिल हैं

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

किसी देश की राजनीति में एक दशक का प्रभुत्व मामूली नहीं है। यह प्रभाव आलोचना और इतिहास के लिहाज से युगीन महत्व को व्याख्यायित करता है। इस लिहाज से देखें तो भारत की बीते एक दशक की यात्रा कई मायने में विलक्षण है। यह पूरा दौर भारतीय राजनीति के केंद्र में नरेन्द्र मोदी के स्थापित होने का है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच केंद्र और राज्य के बदले सत्ता समीकरण से आगे वैचारिक एवं ऐतिहासिक तौर पर जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह कि इस दौरान भारत के संघीय ढांचे को लेकर कई तरह की आपवादिकता खंडित हुई है। इस खंडन से आगे जो बात स्थापित हुई है, वह यह कि अब जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के प्रदेशों से लेकर लक्षद्वीप या गोवा की चर्चा के लिए अलग से किसी डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं। आज ये सब भारत की अखंडता और उसकी सम्मानिकता को बराबरी के साथ मजबूत करते हैं।

पिछले कुछ समय में ऐसे कई संदर्भ और घटनाक्रम सामने आए हैं, जब भारतीयता के डीएनए को लेकर समझ की नई चीजें पैदा हुई हैं। खासतौर पर हाल के दिनों में दो ऐसे मामले सामने आए, जब यह जाहिर हुआ कि दशकों तक भारतीय मुख्यधारा से तकरीबन कटे रहे क्षेत्र आज किस तरह महत्व पा रहे हैं। इस लिहाज से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरा खासतौर पर महत्वपूर्ण है। मोदी ने इस द्वीप पर बिताए पलों की तस्वीरों के साथ साझा किया। उन्होंने लक्षद्वीप को एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। दिलचस्प है कि इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर लक्षद्वीप की मालदीव से तुलना शुरू हो गई। परंतु मालदीव की एक मंत्री ने जब इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की प्रशंसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बात काफी आगे बढ़ गई। देखते-देखते यह मामला भारतीय गौरव और अस्मिता से जुड़ गया। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक के बाद एक आए सैकड़ों पोस्ट में भारतीयों ने मारीशस की मंत्री की बखिया उधेड़ी, वहीं दुनिया ने भारतीय एकता और अखंडता की ताकत देखी। करोड़ों भारतीयों का राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रबोध इतना प्रभावी रहा कि मंत्री को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। बड़ी बात यह कि यह सब किसी कूटनीतिक हस्तक्षेप के बगैर हुआ।

ऐसा ही दूसरा अवसर तब आया जब गोवा के मुख्यमंत्री डा. प्रमोद सावंत अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। हिंदू आस्था और परंपरा के साथ गोवा के इस जुड़ाव ने सबको दंग किया।

वस्तुतः जिस गोवा के सांस्कृतिक आकर्षण को लेकर कभी पुलेक पदासी जैसे दिग्गज कहते थे कि समुद्र के किनारे भारत का यह हिस्सा वेस्टर्न कल्चर का ईस्टर्न गेटवे है, वह गोवा आज सनातन और अध्यात्म के साथ अपने सांस्कृतिक डीएनए पर नाज कर रहा है। गोवा का आध्यात्मिक राष्ट्रबाद के टैंपलेट के रूप में चर्चा में आना बीते एक दशक में भारत में आए बड़े परिवर्तन की गवाही है। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग दो सौ साल शासन किया, लेकिन गोवा के लोगों ने सदे चार सौ साल तक पुर्तगालियों को सहा। गोवा के मुख्यमंत्री इतिहास के इस पृष्ठ को खोलते हुए गर्व के साथ आज यह बात कहते हैं कि शताब्दियों लंबे विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप के बावजूद गोवा का कल्चरल कन्जर्जन न हो सका, वह लगातार भारतीय परंपरा के साथ जुड़ा रहा।

अंडमान-निकोबार स्थित कई छोटे-छोटे द्वीपों को विकसित किया जा रहा है। फाइल

भारत और भारतीयता से जुड़े नव विमर्श में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख भी जरूरी है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री के हाल के कश्मीर दौरे की चर्चा उल्लेखनीय है। श्रीनगर में जब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के लोगों के जीवन में आए बदलाव की चर्चा की तो इसके कई राजनीतिक-अराजनीतिक मायने निकाले गए। दिलचस्प है कि कश्मीर में आए बदलाव और खूबसूरत का एक सिरा गोवा से भी जुड़ता है। टूबलाग की दुनिया के लोग इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जिस कश्मीर को धरती पर जन्नत माना जाता है, वहां दुनिया भर से सैलानी अब बेखौफ पहुंच रहे हैं।

आखिर में बात उन द्वीपों की, जिनका उपयोग केवल मानचित्र पर भारत के भौगोलिक विस्तार को दिखाने भर के लिए होता रहा। भूले नहीं हैं लोग उस ऐतिहासिक क्षण को जब गत वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र सम्मानित बलिदानियों के नाम पर किया गया। देश की एकता व अखंडता के लिए बलिदान का इतिहास अजर भारत की विरासत से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का न केवल हौसला दे रहा है, बल्कि इसके साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का नया आख्यान भी रच रहा है।

****